Kamal.Sandesh kamalsandesh.org KamalSandesh

कमल संदेश

वर्ष-18, अंक-05 01-15 मार्च, 2023 (पाक्षिक) ₹20

राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में प्रधानमंत्री का जवाब

‘भाजपा एक प्रो-एक्टिव, प्रो-रिस्पॉन्सिव एवं प्रो-रिस्पॉन्सिबल राजनीतिक दल है’

विशेष साक्षात्कार: केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण

उडुपी में 20 फरवरी, 2023 को जिला बूथ समिति समावेश के दौरान कर्नाटक भाजपा इकाई ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा का स्वागत किया

पूर्व मेदिनीपुर (पश्चिम बंगाल) में 12 फरवरी, 2023 को एक जनसभा के दौरान अभिवादन स्वीकार करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

कोहिमा (नागालैंड) में 14 फरवरी, 2023 को 'नागालैंड दृष्टि पत्र 2023' जारी करने के बाद सभा को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

तुरा, वेस्ट गारो हिल्स (मेघालय) में 17 फरवरी, 2023 को एक विशाल जनसभा को संबोधित करते केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

सोनीपत (हरियाणा) में 14 फरवरी, 2023 को कार्यकर्ता बैठक के दौरान दीप प्रज्वलित करते केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

बेंगलुरु में 15 फरवरी, 2023 को एयरो इंडिया शो 2023 के दौरान लगभग 80,000 करोड़ रुपये की 266 साझेदारियों के बाद 'बंधन समारोह' को संबोधित करते रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सह संपादक
संजीव कुमार सिन्हा
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
भोला राय

डिजिटल मीडिया
राजीव कुमार
विपुल शर्मा

सदस्यता एवं वितरण
सतीश कुमार

इ-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
फोन: 011-23381428, फैक्स: 011-23387887
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 भाजपा कार्यकर्ता जमीन से जुड़कर कर्नाटक को मजबूत करें : जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 20 फरवरी, 2023 को कर्नाटक के उडुपी में भाजपा के जिला बूथ समिति समावेश को संबोधित किया और उनसे कर्नाटक के विकास के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा...

08 राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में प्रधानमंत्री का जवाब

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का नौ फरवरी...

13 नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का दृष्टि पत्र जारी

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 14 फरवरी, 2023 को कोहिमा में नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी...

30 प्रधानमंत्री ने तुर्किए और सीरिया में 'ऑपरेशन दोस्त' में शामिल एनडीआरएफ कर्मियों के साथ की बातचीत

भूकंप प्रभावित तुर्किए और सीरिया में 'ऑपरेशन दोस्त' के तहत राहत व बचाव कार्य कर...

31 प्रधानमंत्री ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का किया उद्घाटन

प्रधानमंत्री ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023...

लेख

मोदी सरकार में भारत की 'सॉफ्ट पावर' खिल रही है / **बैजयंत जय पांडा** 24

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर का विकास / **तरुण चुघ** 25

महाशक्ति होने के मार्ग पर मील का पत्थर — बजट 2023-24
गोपाल कृष्ण अग्रवाल 27

श्रद्धांजलि

भाजपा के वरिष्ठ नेता और गुजरात के पूर्व राज्यपाल ओमप्रकाश कोहली का निधन 21

विशेष साक्षात्कार

'बजट - भारत@100 और भारत के अमृत काल के लिए कार्य-योजना को प्रतिबिंबित करता है' / **निर्मला सीतारमण** 10

अन्य

प्रधानमंत्री ने 'हरित विकास' पर बजट उपरांत वेबिनार को किया संबोधित 09

छात्राओं के लिए केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा : जगत प्रकाश नड्डा 12

ममता सरकार भ्रष्टाचार और घोटाले की जननी है 14

केंद्रीय गृह मंत्री का महाराष्ट्र एवं नागालैंड प्रवास 15

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली-दौसा-लालसोट खंड राष्ट्र को समर्पित 16

लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (एसएसएलवी) का सफल प्रक्षेपण 18

मोदी स्टोरी 20

कमल पुष्प 20

प्रधानमंत्री ने दिल्ली स्थित मेजर ध्यान चंद राष्ट्रीय स्टेडियम में 'आदि महोत्सव' का किया उद्घाटन 22

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, प्लॉट नं.-8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.)-201306 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

सोशल मीडिया से

नरेन्द्र मोदी

हमारी महान आदिवासी परंपरा से पूरी दुनिया यह सीख ले सकती है कि प्रकृति से संसाधन लेकर भी कैसे उसका संरक्षण और संवर्धन किया जा सकता है।

(16 फरवरी, 2023)

जगत प्रकाश नड्डा

पश्चिम बंगाल के पूरबा मेदिनीनगर की जनसभा में जन-जन के उत्साह व स्नेह से अभिभूत हूं। इस पुण्यभूमि ने देश की राजनीतिक संस्कृति को वैचारिक दिशा दी है। तृणमूल की संकीर्ण राजनीति के कारण जनता अत्याचार व अव्यवस्था से पीड़ित है। भाजपा प्रदेश में सुशासन की स्थापना के लिए संकल्पित है। (12 फरवरी, 2023)

अमित शाह

मोदीजी एक कर्मठ कार्यकर्ता, एक स्टेट्समैन, एक टीम लीडर, एक भावुक राजनेता, एक निडर सेनापति और एक उपभोग शून्य स्वामी हैं। हम सब कार्यकर्ताओं के लिए सौभाग्य की बात है कि हम मोदीजी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। (19 फरवरी, 2023)

राजनाथ सिंह

साल 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले में अपना बलिदान देने वाले बहादुर जवानों के प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यह देश वीरगति को प्राप्त हुए इन जवानों के साहस और बलिदान को नमन करता है। उनके परिवारों के साथ पूरा देश मज़बूती के साथ खड़ा है। (14 फरवरी, 2023)

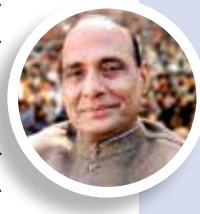

बी.एल. संतोष

कम्युनिस्ट शासन केरल की सबसे बड़ी भूल है। आपका जीएसटी राष्ट्रीय औसत का आधा है। देश के कोने-कोने में केरल के छात्र हैं। ऐसा क्यों है..? औद्योगिक वातावरण संकट में है। हिंसा और तुष्टीकरण के वातावरण के अलावा और क्या बनाया है आपने...? शून्य।

(13 फरवरी, 2023)

सुधा यादव

भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी के नेतृत्व में जी-20 दुनिया में वैश्विक समृद्धि व लोककल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने जा रहा है।

(11 फरवरी, 2023)

कमल संदेश परिवार की ओर से
सुधी पाठकों को
होली (8 मार्च)
की हार्दिक शुभकामनाएं!

संपादकीय

वैश्विक 'ग्रोथ इंजन' बनकर उभरा भारत

जहां विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं कोविड-19 वैश्विक महामारी एवं रूस-यूक्रेन युद्ध का मार झेल रही हैं, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया को अपनी चमक से प्रभावति कर रही है। इंटरनेशनल मोनेटरी फंड (आईएमएफ) के आंकड़ों को यदि देखे तब वर्ष 2023 में भारत वैश्विक विकास में 15 प्रतिशत योगदान देने वाला है। इतना ही नहीं, आज जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी का अनुमान है, भारतीय अर्थव्यवस्था 6 प्रतिशत से भी अधिक दर से बढ़ने वाली है। कोविड-19 वैश्विक महामारी की चुनौतियों का जिस कुशलता से भारत ने सामना किया तथा इस संकट भरे दौर में अन्य देशों की सहायता की, उसकी हर ओर भूरि-भूरि प्रशंसा हो रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का हर चुनौती को अवसर में बदलने का आह्वान एक राष्ट्रीय संकल्प में परिवर्तित हुआ। यह उनके दूरदर्शी एवं करिश्माई नेतृत्व का ही परिणाम था कि इस दौर में अनेक सुधार किए गए, 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' जैसे कदमों से गरीब से गरीब व्यक्ति को राहत दी गई तथा 'आत्मनिर्भर भारत' पैकेज के माध्यम से एमएसएमई एवं अन्य संकटग्रस्त क्षेत्रों को मजबूती दी गई। इस कठिन दौर में 'मेड इन इंडिया' टीकों के उत्पादन तथा 220 करोड़ से भी अधिक निःशुल्क टीकों के अलावा अर्थव्यवस्था के व्यापक डिजिटलीकरण के परिणामस्वरूप आज विश्व का 40 प्रतिशत डिजिटल लेन-देन भारत में हो रहा है। आज, जब भारत विश्व का 'ग्रोथ इंजन' बनकर उभरा है तथा इसके महत्व को आईएमएफ, विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थान स्वीकार रहे हैं, देश विश्वभर में आशा की किरण बनकर उभरा है।

> **आज, जब भारत विश्व का 'ग्रोथ इंजन' बनकर उभरा है तथा इसके महत्व को आईएमएफ, विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थान स्वीकार रहे हैं, देश विश्वभर में आशा की किरण बनकर उभरा है**

आज, जब भारत से पूरे विश्व की आशा एवं अपेक्षा जग रही है, एयर इंडिया द्वारा अमेरिका एवं फ्रांस से 470 विमानों की खरीदी से यह स्पष्ट है कि भारत में अब अपार संभावनाएं हैं। इस खरीदी का स्वागत करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति श्री जो बाइडेन ने अपने ट्वीट के माध्यम से यह आशा व्यक्त की कि इससे अमेरिका के 44 राज्यों में 10 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कांग्रेस-यूपीए के दौर में दसवें स्थान पर रही भारत की अर्थव्यवस्था पिछले नौ वर्षों में पांचवें स्थान पर आने के साथ-साथ इसकी प्रति व्यक्ति आय भी दुगुनी से भी अधिक हो चुकी है। आज भारतीय अर्थव्यवस्था सभी मानकों पर मजबूती से खड़ी है तथा विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तीव्र विकास दर वाली अर्थव्यवस्था बन गई है। बजट 2023-24 को परिवर्तनकारी कदम के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें हर क्षेत्र में भारी निवेश का प्रावधान है। एक ओर जहां पिछले नौ वर्षों में देश के बजट में दुगुनी से भी अधिक वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर विभिन्न मंत्रालयों के लिए आवंटन कई गुणा अधिक बढ़ा दिए गए हैं। जहां पूरा विश्व उच्च मुद्रास्फीति दर के दबाव में है, मोदी सरकार ने इसे नियंत्रित कर पिछले नौ वर्षों में औसतन 4.93 प्रतिशत पर रखा है जबकि कांग्रेस-नीत यूपीए के दौर में औसतन मुद्रास्फीति की दर 8.45 प्रतिशत रही थी। जहां कांग्रेस नीत यूपीए के दौर में सर्वाधिक 11.94 प्रतिशत मुद्रास्फीति की दर गयी थी, वहीं भाजपा-नीत राजग के दौर में यह 7.8 प्रतिशत रही है और वह भी कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण। अथक प्रयास, न डिगने का संकल्प, विभिन्न सुधार एवं राष्ट्रीय एकजुटता के कारण आज भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में अग्रणी एवं सर्वसमावेशी तो बनी ही है, साथ ही गरीब, वंचित, अनु. जाति एवं जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला एवं युवाओं का व्यापक सशक्तीकरण भी हुआ है।

विश्व को मानव कल्याण के कार्य की प्रेरणा देने वाला 'वसुधैव कुटुंबकम्' के मंत्र की गूंज 'ऑपरेशन दोस्त' में भी सुनाई पड़ी है। इस ऑपरेशन के अंतर्गत तुर्की एवं सीरिया में भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में भारतीय आपदा राहत टीम ने अपनी सेवाएं देकर पूरे विश्व में सहायता एवं मित्रता का संदेश दिया है। कोविड-19 वैश्विक महामारी, प्राकृतिक आपदाओं, रूस-यूक्रेन युद्ध, श्रीलंका में वित्तीय संकट, शांति स्थापना जैसे कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते हुए संकटग्रस्त देशों का सहायता पहुंचाकर भारत मानवता की सेवा में सदैव तत्पर है। आज जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सुदृढ़ एवं प्रो-एक्टिव नेतृत्व में जी-20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, यह विश्व के अनेक देशों का विश्वसनीय मित्र के रूप में उभरा है। ■

shivshaktibakshi@kamalsandesh.org

भाजपा कार्यकर्ता जमीन से जुड़कर कर्नाटक को मजबूत करें : जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 19 फरवरी से 21 फरवरी, 2023 तक कर्नाटक का तीन दिवसीय प्रवास किया। इस दौरान उन्होंने जिला बूथ समिति समावेश, सुपारी उत्पादकों के साथ संवाद एवं बुद्धिजीवी सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश के विकास के लिए पुनः भाजपा सरकार बनाने का आह्वान किया

बूथ समिति समावेश

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 20 फरवरी, 2023 को कर्नाटक के उडुपी में भाजपा के जिला बूथ समिति समावेश को संबोधित किया और उनसे कर्नाटक के विकास के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करने का आह्वान करते हुए एक बार पुनः पूर्ण बहुमत वाली भाजपा की डबल इंजन सरकार बनाने का आह्वान किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश की एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसकी वैचारिक पृष्ठभूमि है, कैडर है, मास फॉलोइंग है। हम अपनी स्थापना काल से ही अपनी विचारधारा पर अटल रहे, अडिग रहे। हमारे संस्थापक मनीषी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जीजी ने धारा 370 को ख़त्म करने को लेकर आंदोलन शुरू किया था और अपने प्राणों की आहुति दी थी। हम इसको लेकर सतत संघर्ष करते रहे और 2019 में प्रधानमंत्रीजी की दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और हमारे गृहमंत्री श्री अमित शाह की कुशल रणनीति के बल पर धारा 370 धाराशायी हुआ। कांग्रेस, सपा, बसपा, राजद, टीएमसी, बीआरएस, डीएमके सहित देश में मौजूद लगभग सभी राजनीतिक दल एक परिवार वाली पार्टी है, लेकिन भाजपा में पार्टी ही परिवार है। भाजपा एक प्रो-एक्टिव, प्रो-रिस्पॉन्सिव और प्रो-रिस्पांसिबल पार्टी है।

उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही 6 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कर्नाटक के ही तुमकुरु में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के हेलीकॉप्टर कारखाने को देश को समर्पित किया। 615 एकड़ में फैली ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री भारत ही नहीं, बल्कि एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री है। यह कर्नाटक और देश में विकास की क्रांति लाएगी। तुमकुरु में साउथ इंडिया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भी लोकार्पण हुआ है। कुछ ही दिन पहले कर्नाटक के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर एशिया का सबसे बड़ा एयरशो हुआ।

उन्होंने कहा कि पिछले साल नवंबर में प्रधानमंत्रीजी ने कर्नाटक को वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी थी। लगभग 5,000 करोड़ रुपये की लागत से कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल - II का लोकार्पण हुआ है। प्रधानमंत्रीजी ने बेंगलुरु के संस्थापक नाद्गुरु कैंपेगौड़ाजी की 108 फीट की कांस्य प्रतिमा का 'स्टैच्यू ऑफ़ प्रोस्पेरिटी' भी अनावरण किया। जून, 2022 में प्रधानमंत्रीजी ने कर्नाटक में लगभग 33,000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं दी। इससे कर्नाटक देश में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ेगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से कर्नाटक में लगभग 9 लाख करोड़ रुपये का निवेश हुआ

है। आज प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कर्नाटक देश में पहले स्थान पर है। भारत के स्पेस सेक्टर में कर्नाटक की हिस्सेदारी लगभग 25 प्रतिशत है। डिफेंस एयरक्राफ्ट के निर्माण का 75 प्रतिशत कर्नाटक में होता है। कोंकण रेलवे का शत-प्रतिशत इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। कर्नाटक में हमारी सरकार ने एससी आरक्षण को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत कर और एसटी का आरक्षण तीन प्रतिशत से बढ़ाकर सात प्रतिशत कर दिया है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री विद्या निधि के तहत 140 करोड़ रुपये खर्च किये गए हैं। मछुआरों को भी क्रेडिट कार्ड दिया गया है। लिंगायत समुदाय को 2डी और वोक्कालिंगा समुदाय को 2सी में शामिल किया गया है। कर्नाटक की 'डबल इंजन' वाली भाजपा सरकार ने 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' की नीति को शत-प्रतिशत धरातल पर उतारा है।

श्री नड्डा ने कहा कि हम सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को अगले 25 साल में हमारा देश कैसा होना चाहिए, उसके लिए समर्पण भाव से जुटकर काम करना चाहिए। भाजपा कार्यकर्ता जमीन से जुड़कर कर्नाटक को मजबूत करें।

सुपारी उत्पादकों के साथ संवाद

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 20 फरवरी, 2023 को कर्नाटक के चिकमंगलुरु में सुपारी उत्पादकों के साथ सीधा संवाद किया और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कर्नाटक की डबल इंजन वाली भाजपा सरकार द्वारा उनके लिए किये जा रहे प्रयासों पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं कर्नाटक के प्रभारी श्री अरुण सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री श्री सीटी रवि और केंद्रीय मंत्री केंद्रीय मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे सहित कई वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारी और गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने ही सुपारी उत्पादकों पर ध्यान दिया है, उनके लिए काम किया है, जबकि अन्य राजनीतिक दलों के लिए केवल और केवल घड़ियाली आंसू बहाया है।

श्री नड्डा ने याद दिलाते हुए कहा कि हमारे वरिष्ठ नेता श्री बीएस येदियुरप्पा ने 1982 में सुपारी उत्पादक किसानों की समस्या दूर करने के लिए 65 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली थी। एरीकानट उपजाने वाले किसानों को न्याय दिलाने के लिए बीएस येदियुरप्पाजी निरंतर संघर्षरत रहे।

उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार ने सामान्य वर्ग के किसानों को कॉपर सल्फेट और लाइम पर 75 प्रतिशत सब्सिडी और आरक्षित वर्ग के किसानों को 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी, ताकि ऊपज को बीमारियों से बचाया जा सके। जिन किसानों के एरिकानट ऊपज कीड़ों से बर्बाद हुए, उन सभी किसानों के लिए 10 करोड़ रुपए का ग्रांट भी दिया गया। लगभग 4 करोड़ रुपए लीफ डिजीज से होने वाले नुकसान के लिए किसानों को दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पूरा प्रयास रहा है कि एरिकानट की ऊपज में कोई समस्या नहीं हो और किसानों को यदि किसी प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है तो उसका समाधान निकाला जाए। उत्तर कर्नाटक में सुपारी को जीआई टैग दिया गया है। उत्तर कर्नाटक के किसानों को इसके लिए मैं बधाई देता हूं।

बुद्धिजीवी सम्मेलन

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कर्नाटक के तीन दिवसीय दौरे के अंतिम दिन 21 फरवरी, 2023 को चिक्कमगलुरु में आयोजित एक बुद्धिजीवी सम्मेलन को संबोधित किया और वहां के बुद्धिजीवी वर्ग के समक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, पिछड़े, युवा एवं महिलाओं के कल्याण के प्रति समर्पित भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित किया। इससे पूर्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक विशाल बाइक रैली को भी हरी झंडी दिखाई, जिसमें हजारों कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया।

श्री नड्डा ने कोरोना काल और रूस-यूक्रेन संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के बाद दुनिया आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है। रूस-यूक्रेन युद्ध कारण दुनिया में सप्लाई चेन बिगड़ गया। इन तमाम झंझावातों के बावजूद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत आर्थिक विकास कर रहा है। जहां भारत की अर्थव्यवस्था 7.4 प्रतिशत की दर से विकास कर रहा है वहीं, अमेरिका की जीडीपी 2.3 प्रतिशत और चीन की जीडीपी 3.3 प्रतिशत पर और फ्रांस की जीडीपी 1.4 प्रतिशत पर ठहरी हुई है। ■

राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में प्रधानमंत्री का जवाब

'हमने राष्ट्रीय प्रगति के साथ क्षेत्रीय आकांक्षाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया है'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का नौ फरवरी को राज्यसभा में जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने अपने उत्तर की शुरुआत राष्ट्रपति जी द्वारा अपने संबोधन में 'विकसित भारत' का विजन प्रस्तुत करके दोनों सदनों का मार्गदर्शन करने के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए की।

श्री मोदी ने कहा कि पहले के समय के विपरीत हमारी सरकार का उद्देश्य नागरिकों के लिए स्थायी समाधान प्रदान करना और उन्हें सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि पहले के समय में भी लोगों की समस्याओं का समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी थी, लेकिन उनकी प्राथमिकताएं और उनके इरादे अलग थे। उन्होंने कहा कि आज हम समस्याओं के स्थायी समाधान की ओर बढ़ रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने पानी के मुद्दे का उदाहरण दिया और समझाया कि प्रतीकात्मकता के बजाय जल अवसंरचना, जल शासन, गुणवत्ता नियंत्रण, जल संरक्षण और सिंचाई नवाचार को तैयार करने के लिए एक समग्र एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसी तरह के उपायों से वित्तीय समावेश, जन धन-आधार-मोबाइल के माध्यम से डीबीटी, पीएम गतिशक्ति मास्टरप्लान के माध्यम से अवसंरचना योजना निर्माण और कार्यान्वयन में स्थायी समाधान तैयार किए गए हैं।

हमारी सरकार का उद्देश्य नागरिकों के सामने आने वाली समस्याओं का स्थायी समाधान प्रदान करना और उन्हें सशक्त बनाना है

श्री मोदी ने कहा कि हम आधुनिक भारत के निर्माण के लिए अवसंरचना, पैमाने और गति के महत्व को समझते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तकनीक की ताकत से देश की कार्य-संस्कृति में बदलाव आया है और सरकार का ध्यान इसकी गति और इसके पैमाने को बढ़ाने पर है।

हमने 'श्रेय' (योग्यता) का मार्ग चुना

श्री मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी 'श्रेय' (योग्यता) और 'प्रिय' (प्रिय) कहा करते थे। हमने 'श्रेय' (योग्यता) का मार्ग चुना है। प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि सरकार ने जो रास्ता चुना है, वह ऐसा नहीं है जहां आराम करना प्राथमिकता है, बल्कि यह रास्ता ऐसा है, जहां हम आम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दिन-रात काम करते हैं।

श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार ने आजादी के अमृत काल में सम्पूर्णता प्राप्ति को हासिल करने का महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने सरकार के उन प्रयासों को दोहराया, जहां देश के प्रत्येक लाभार्थी तक लाभ शत-प्रतिशत पहुंच रहा है। श्री मोदी ने कहा कि यही सच्ची धर्मनिरपेक्षता है। यह भेदभाव और भ्रष्टाचार को भी समाप्त करता है।

श्री मोदी ने कहा कि दशकों से आदिवासी समुदायों के विकास की उपेक्षा की गई थी। हमने उनके कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में आदिवासी कल्याण के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया गया था और आदिवासी कल्याण की दिशा में ठोस प्रयास किए गए थे।

छोटे किसान भारत के कृषि क्षेत्र की रीढ़

प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि छोटे किसान भारत के कृषि क्षेत्र की रीढ़ हैं। हम उनके हाथ मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि लंबे समय तक छोटे किसानों की उपेक्षा की गई। वर्तमान सरकार ने उनकी जरूरतों पर ध्यान दिया और छोटे विक्रेताओं एवं कारीगरों के साथ-साथ छोटे किसानों के लिए कई अवसर पैदा किए।

प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तीकरण की दिशा में उठाए गए कदमों के बारे में भी विस्तार से बताया और देश में महिलाओं के जीवन के हर चरण में सशक्तीकरण, गरिमा सुनिश्चित करने और जीवन को आसान बनाने से संबंधित सरकार की विभिन्न पहल के बारे में बात की।

श्री मोदी ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों और अन्वेषकों की विशेषज्ञता की बदौलत भारत दुनिया का फार्मा हब बनता जा रहा है। उन्होंने कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह बात इस संदर्भ में कही कि कुछ लोगों ने भारत के वैज्ञानिकों, अन्वेषकों और वैक्सीन निर्माताओं को निराश करने की कोशिश की थी।

श्री मोदी ने अटल नवाचार मिशन और टिंकरिंग लैब जैसे उपायों के माध्यम से विद्यार्थियों में वैज्ञानिक समझ विकसित करने की बात कही। उन्होंने सरकार द्वारा सृजित अवसरों का पूरी तरह से

उपयोग करने एवं निजी उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए युवाओं और वैज्ञानिकों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सफल हुए हैं और आम नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं।

भारत डिजिटल लेन-देन में पूरे विश्व में अग्रणी

श्री मोदी ने कहा कि भारत आज भी डिजिटल लेन-देन में पूरे विश्व में अग्रणी बना हुआ है। डिजिटल इंडिया की सफलता ने आज पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। उन्होंने उस दौर को स्मरण किया जब भारत मोबाइल फोन का आयात किया करता था, जबकि आज हमें इस बात पर काफी गर्व है कि भारत से दूसरे देशों को मोबाइल फोन निर्यात किए जा रहे हैं।

श्री मोदी ने कहा कि यह हमारा दृढ़ संकल्प है कि भारत वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' बन जाएगा। उन्होंने यह बात दोहराई कि सरकार ने उन अवसरों का सदुपयोग करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जिनकी हम तलाश करते रहे थे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन का समापन करते हुए कहा कि भारत बड़ी छलांग लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और भारत अब पीछे मुड़कर नहीं देखता है।

मुख्य बातें

- हम आधुनिक भारत के निर्माण के लिए अवसंरचना, पैमाने और गति के महत्व को समझते हैं
- हमारी सोच खंडित नहीं है, हम प्रतीकवाद में विश्वास नहीं करते
- हम सफल हुए हैं और हम आम नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं
- डिजिटल इंडिया की सफलता ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है
- हमारा संकल्प है कि 2047 तक देश 'विकसित भारत' बने ■

प्रधानमंत्री ने 'हरित विकास' पर बजट उपरांत वेबिनार को किया संबोधित

भारत ने लक्ष्य तिथि से 9 साल पहले गैर-जीवाश्म ईंधन से 40 प्रतिशत योगदान का लक्ष्य प्राप्त कर लिया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 23 फरवरी को 'हरित विकास' पर बजट उपरांत वेबिनार को संबोधित किया। यह वेबिनार केन्द्रीय बजट 2023 में घोषित की गई विभिन्न पहल के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विचारों एवं सुझावों की खोज के उद्देश्य से सरकार द्वारा आयोजित 12 बजट उपरांत वेबिनारों की श्रृंखला की पहली कड़ी है।

सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 के बाद देश में प्रस्तुत किए गए सभी बजट वर्तमान चुनौतियों का समाधान खोजने के साथ-साथ नए युग के सुधारों को आगे बढ़ाते रहे हैं।

श्री मोदी ने हरित विकास और ऊर्जा संचरण के तीन स्तंभों का उल्लेख किया। इन स्तंभों में पहला, नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना; दूसरा, अपनी अर्थव्यवस्था में जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करना और आखिरी, देश को तेजी से गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ाना शामिल है। इस रणनीति ने पिछले कुछ वर्षों के बजट में इथेनॉल ब्लेंडिंग, पीएम कुसुम योजना, सोलर मैन्यूफैक्चरिंग के लिए प्रोत्साहन, रूफटॉप सोलर स्कीम, कोयला गैसीकरण और बैटरी स्टोरेज जैसे उपायों की घोषणाओं को रेखांकित किया है।

पिछले वर्षों के विभिन्न बजटों में की गई महत्वपूर्ण घोषणाओं को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने इस वर्ष के बजट में उद्योगों के लिए हरित ऋण, किसानों के लिए पीएम प्रणाम योजना, गांवों के लिए गोबर-धन योजना, शहरों के लिए वाहन स्क्रैपिंग नीति, हरित हाइड्रोजन और आर्द्रभूमि संरक्षण जैसी योजनाओं पर प्रकाश डाला।

श्री मोदी ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि ये घोषणाएं भावी पीढ़ी के उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला हैं और उसके लिए मार्ग प्रशस्त करती हैं।

उन्होंने कहा कि भारत 2014 के बाद से नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तेज गति से बढ़ाने के मामले में विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे आगे रहा है। श्री मोदी ने कहा कि जब नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की बात आती है तो भारत का ट्रैक रिकॉर्ड समय से पहले उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने लक्ष्य तिथि से 9 साल पहले स्थापित बिजली क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधन से 40 प्रतिशत योगदान का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि भारत ने समय से 5 महीने पहले पेट्रोल में 10 प्रतिशत इथेनॉल मिलाने के लक्ष्य को हासिल कर लिया है और जोर देकर कहा कि देश 2030 के बजाय 2025-26 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य हासिल करने का प्रयास करेगा। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि 2030 तक 500 जीडब्ल्यू की क्षमता प्राप्त की जाएगी। ■

विशेष साक्षात्कार

'बजट - भारत@100 और भारत के अमृत काल के लिए कार्य-योजना को प्रतिबिंबित करता है'

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 01 फरवरी, 2023 को संसद में 'अमृत काल' का पहला बजट पेश किया। कमल संदेश के एसोसिएट एडिटर राम प्रसाद त्रिपाठी के साथ बातचीत में केंद्रीय वित्त मंत्री ने विस्तार से बताया कि कैसे दुनिया भारतीय अर्थव्यवस्था को भारत की आजादी के 75वें वर्ष में एक 'उज्ज्वल सितारे' के रूप में मान्यता दे रही है। प्रस्तुत है इस बातचीत के प्रमुख अंशः

अमृत काल के इस पहले बजट से आप कौन से प्रमुख उद्देश्यों को हासिल करना चाहती थीं?

बजट अनिवार्य रूप से भारत@100 और भारत के अमृत काल के लिए कार्ययोजना को प्रतिबिंबित करता है। हम एक समृद्ध और समावेशी भारत की कल्पना करते हैं, जिसमें विकास का लाभ सभी क्षेत्रों और नागरिकों विशेष रूप से हमारे युवाओं, महिलाओं, किसानों, ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तक पहुंचे।

भारत के 'अमृत काल' के पहले बजट के लिए कई कारक अनुकूल और सकारात्मक हैं जैसे जनसांख्यिकी, बुनियादी ढांचे का निर्माण या आपूर्ति श्रृंखलाओं का जो वैश्विक स्तर पर पुनर्गठन हो रहा है।

यह बजट एक आकर्षक दृष्टिकोण और रणनीति प्रस्तुत करता है, जो इस विश्वास को और मजबूत करता है। पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी और मध्यम वर्ग पर कर के बोझ में कमी के माध्यम से निकट अवधि के विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हुए, यह उन तकनीकी रुझानों को भी संबोधित करता है जिन पर भारत को विकास के अपने अगले चरण की योजना बनाते समय विचार करना चाहिए। हमने सरकारी खर्च में सुधार किया है और सरकार निवेश को आकर्षित करने के लिए बड़े कदम उठा रही है, जिससे आने वाले वर्षों में विकास को गति मिलेगी।

कोविड-19 महामारी के बाद दुनिया भर में मंदी एवं रूस-यूक्रेन युद्ध जैसी सभी बाधाओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 7 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। मोदी सरकार के इस उच्च विकास के क्या कारण हैं?

मोदी सरकार की सोची-समझी नीतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था ने विपरीत वैश्विक परिस्थितियों का दृढ़ता से मुकाबला किया है।

व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और कमजोर परिवारों की रक्षा करने के उद्देश्य से कोविड महामारी के दौरान सरकार की नीति प्रतिक्रिया को सावधानीपूर्वक डिजाइन और लक्षित किया गया। इसमें मांग और आपूर्ति के दोनों पक्षों के सुधार शामिल हैं।

भारत अवसंरचना जैसे सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों का निर्माण तीव्र गति से कर रहा है। हमने महामारी के दौरान 80 करोड़ भारतीयों को निःशुल्क भोजन दिया है। हमने 2 अरब से अधिक कोविड टीके लगाए हैं और उनमें से एक बड़ा भाग निःशुल्क है। इससे पहले मानव इतिहास में शायद ही कभी ऐसे प्रयास देखने को मिले होंगे।

मजबूत कर संग्रह, पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार और सकारात्मक नीति निर्धारण के साथ-साथ विवेकपूर्ण व्यापक आर्थिक प्रबंधन ने भारत की अर्थव्यवस्था को वित्तीय संकट से निपटने के लिए लचीला बनाने में मदद की है।

बजट में पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी के पीछे क्या विचार है? यह अर्थव्यवस्था की विकास संभावनाओं में किस प्रकार मदद करने जा रहा है?

- बजट में पूंजी निवेश के लिए 10 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो लगातार तीसरे वर्ष 33 प्रतिशत की भारी वृद्धि है, इसके माध्यम से विकास क्षमता और रोजगार सृजन, निजी निवेश में बढ़ोतरी और भारत को सही मायने में आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी।
- अवसंरचना निर्माण से लोगों वस्तुएं को स्थानांतरित करना आसान और अधिक सुविधाजनक हो जाएगा, सेवाओं और श्रम में सुधार होगा, स्थानीय आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा और नए रोजगार सृजित होंगे। यह मध्यम अवधि में समग्र अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण गुणात्मक प्रभाव सुनिश्चित करेगा, जिसके परिणामस्वरूप राज्यों का आर्थिक विकास होगा।

इस साल के बजट में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई प्रावधान किये गये हैं। क्या आपको लगता है कि ये आवंटन ग्रामीण भारत की ढांचागत आवश्यकताओं को भी बदल देंगे?

यह बजट कृषि और सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की धुरी बनाएगा। सरकार सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य भंडारण योजना - 'भंडारण क्षमता' लेकर आयी है। बजट में नई प्राथमिक सहकारी समितियों के गठन की महत्वाकांक्षी योजना की भी घोषणा की गई है। इससे खेती के साथ दूध और मछली उत्पादन के क्षेत्र का विस्तार होगा। किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को उनकी उपज का बेहतर

मूल्य मिलेगा।

- इस बजट में किसानों के लिए कई कदम उठाए गए हैं। हमने कृषि ऋण की उपलब्धता के लिए 20 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है। हमने उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए गुणवत्तापूर्ण और रोग मुक्त रोपण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए 2,200 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
- हमने प्राकृतिक खेती, एग्री-स्टार्टअप और एग्री-टेक के लिए आवंटन किया है जो किसानों के लिए फायदेमंद होगा। मोदी सरकार द्वारा शुरू किए गए पीएम-किसान के तहत 11.3 करोड़ किसानों को उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए कवर किया गया है।
- हमने किसानों के लिए एमएसपी में लगातार बढ़ोतरी की है। 2018 से सभी अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत का 1.5 गुना तय किया गया है।

हाल के दिनों में वैश्विक महामारी ने भारत में मध्यम वर्ग और विशेष रूप से युवाओं को प्रभावित किया है। क्या यह बजट उनके लिए बहुप्रतीक्षित राहत और रोजगार सृजित करने वाला है?

'अमृत काल' का पहला बजट विकसित भारत की आकांक्षाओं और संकल्पों की मजबूत नींव रखता है। यह अमृत काल हमारी 'अमृत पीढ़ी' के लिए अत्यंत लाभकारी होगा।

पिछले कुछ वर्षों में हमारी सरकार ने विकास रणनीति के रूप में नवाचार को प्राथमिकता दी है। नवाचार हमारी 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के केंद्र में है, जिसके तीन स्पष्ट उद्देश्य हैं-

1. मेक इन इंडिया,
2. भारत में नवाचार और
3. भारतीय अर्थव्यवस्था को बदलना

यह युवाओं के लिए करोड़ों अवसर पैदा करेगा।

- 'पीएम कौशल विकास योजना 4.0' के तहत उद्योग 4.0 के अनुरूप नए युग के पाठ्यक्रम जैसे कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, मेकाटॉनिक्स, आईओटी, 3डी प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल्स को अगले तीन वर्षों के भीतर शुरू किया जाएगा, जिसके माध्यम से लाखों युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।
- युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 'कौशल भारत अंतरराष्ट्रीय केंद्र' स्थापित किए जाएंगे। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों का जीवंत तरीके से विकास किया जाएगा। 'देखो अपना देश' पहल के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट कौशल और उद्यमिता विकास को समन्वित किया जाएगा।

नई कर व्यवस्था के तहत नए स्लैब और दरों के साथ मध्यम वर्ग को कर राहत दी गई है। अब तक प्रत्येक करदाता आयकर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत कटौती का लाभ नहीं उठा सकता था, लेकिन नई कर व्यवस्था ऐसे कई करदाताओं को लाभान्वित करती है और उन्हें अपने तरीके से निवेश करने की अधिक स्वतंत्रता देती है। करदाताओं के लिए नई कर व्यवस्था को सरल बनाया गया है। अब नागरिकों को 7 लाख से कम आय होने पर टैक्स नहीं देना होगा। हमने 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन पेश किया है, बेसिक टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गयी है। इन प्रावधानों से नागरिकों के हाथों में अधिक पैसा आएगा, जो उच्च निवेश क्षमता को बढ़ावा देगा।

बजट में पर्यावरण और हरित विकास की चिंता 'हरित हाइड्रोजन मिशन' पर अधिक जोर तथा अन्य कदमों से स्पष्ट होती है। इसको लेकर आगे का रोडमैप क्या है?

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली के आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए 'लाइफ' या पर्यावरण के लिए जीवन शैली का एक दृष्टिकोण दिया है। भारत हरित औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन की शुरुआत करने के लिए 2070 तक 'पंचामृत' और शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए मजबूती से आगे बढ़ रहा है। यह बजट हरित विकास पर हमारे फोकस पर आधारित है।

हाल ही में 19,700 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू किया गया राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन बदलती अर्थव्यवस्था को कम कार्बन उत्सर्ज में सुविधा प्रदान करेगा, जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करेगा और देश को इस उभरते हुए क्षेत्र की प्रौद्योगिकी और बाजार का नेतृत्व करने में मदद करेगा। हमारा लक्ष्य 2030 तक 5 एमएमटी के वार्षिक उत्पादन तक पहुंचना है। यह बजट पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के माध्यम से ऊर्जा संक्रमण और शुद्ध शून्य उद्देश्यों एवं ऊर्जा सुरक्षा में पूंजी निवेश के लिए 35,000 करोड़ रुपये प्रदान करता है।

यह ऐतिहासिक बजट माननीय प्रधानमंत्रीजी के 'अमृत काल' के दृष्टिकोण और भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व मंच पर स्थापित करने में कैसे मदद करेगा?

भारत उच्चतम विकास दर के साथ दुनिया में एक 'ब्राइट स्पॉट' है। पिछले नौ वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है और हमारी अर्थव्यवस्था बढ़कर 10वें स्थान से, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गयी है। सरकार ने पूंजीगत व्यय पर लगातार जोर दिया है, जिससे औद्योगिक विकास के लिए सस्ते लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्बाध कनेक्टिविटी को सुनिश्चित किया जा सकेगा। व्यापार में सुगमता के लिए कई सुधार प्रस्तावित किए गए हैं।

पिछले वर्षों में सरकार द्वारा लागू की गयी पीएलआई योजनाओं, बुनियादी ढांचे के निर्माण और अन्य सुधारों के कारण भारत को एक विनिर्माण केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। इन सभी ने भारत को एक आकर्षक निवेश गंतव्य बना दिया है और पिछले दो वित्तीय वर्षों में एफडीआई के माध्यम से 160 बिलियन डॉलर से अधिक प्राप्त हुए हैं। वैश्विक बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपनाई जा रही ईयू+1 और चीन+1 रणनीतियों से भी भारत को लाभ होगा। ■

छात्राओं के लिए केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा : जगत प्रकाश नड्डा

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 15 फरवरी, 2023 को शिलांग में मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का 'दृष्टि पत्र' जारी किया। पार्टी ने अपने 'दृष्टि पत्र' में प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एसटीएफ गठित करने की घोषणा की। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस अवसर पर महिला और युवा सशक्तीकरण की कई योजनाओं का वादा किया।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने छात्राओं को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा और अगर पार्टी सत्ता में आती है तो कॉलेज जाने वाली छात्राओं मेधावी को मुफ्त स्कूटी प्रदान की जाएगी। विदित हो कि प्रदेश में इस महीने की 27 तारीख को मतदान होगा। दृष्टि पत्र के प्रमुख बिंदुः

सुशासन

- हम भ्रष्टाचार के सभी मामलों की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेष कार्य बल की स्थापना करेंगे, ताकि सरकारी सेवाओं में किसी भी देरी, दोष या इनकार के खिलाफ त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की जा सके।
- हम मेघालय में सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग लागू करेंगे।

संस्कृति और पर्यटन

- हम राज्य की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक अत्याधुनिक जनजातीय संग्रहालय की स्थापना में तेजी लाएंगे।
- हम गारो हिल्स, खासी हिल्स और जैंतिया हिल्स क्षेत्रों के बहादुर स्वतंत्रता सेनानी पा तोगन नेंगमिंजा, यू. तिरोत सिंह सीयेम और यू कियांग नांगबाह के सम्मान में जनजातीय युद्ध स्मारक स्थापित करेंगे।
- मेघालय को एक प्रमुख राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए हम 1000 करोड़ रुपये का निवेश कर मेघालय की पर्यटन अर्थव्यवस्था का विस्तार करेंगे।

किसान सशक्तीकरण

- हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत वार्षिक वित्तीय सहायता को मौजूदा 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये प्रति वर्ष करेंगे।
- हम सभी भूमिहीन किसानों को मुख्यमंत्री भूमिहीन किसान योजना के तहत 3,000 रुपये प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे।
- हम मछुआरा आय सहायता योजना के तहत सभी मछुआरों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे।

महिला सशक्तीकरण

- 'का फन नोंगलैट योजना' को लागू किया जाएगा और इसके तहत बालिका के जन्म पर 50,000 रुपये का बांड प्रदान किया जाएगा।
- हम केजी से पीजी तक की सभी छात्राओं को निःशुल्क, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे।
- हम आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की सभी मेधावी कॉलेज जाने वाली छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी प्रदान करेंगे।
- हम पुलिस बल पर विशेष ध्यान देते हुए सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करेंगे।

युवा सशक्तीकरण

- हम कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेंगे और अगले 5 वर्षों में दो नए एसईजेड, औद्योगिक इकाइयां, एक अतिरिक्त आईटी पार्क, बैंकिंग और आतिथ्य उद्योग स्थापित करके 3.5 लाख स्वरोजगार के अवसर पैदा करेंगे।
- हम बेरोजगार स्नातकों को उच्च शिक्षा या सरकारी नौकरियों के लिए तैयार करने में मदद करने के लिए 1 वर्ष की अवधि के लिए 1,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए करनेश मारक युवा सहायता योजना शुरू करेंगे।

सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं

- 'आयुष्मान भारत योजना' के तहत प्रति परिवार वार्षिक बीमा कवर को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया जाएगा।
- हम प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों और अन्य स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 2,500 करोड़ रुपये के निवेश के साथ मेघालय हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू करेंगे। ■

'दृष्टि पत्र नागालैंड की महत्वाकांक्षाओं, इच्छाओं और आकांक्षाओं को दर्शाता है'

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 14 फरवरी, 2023 को कोहिमा में नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का 'दृष्टि पत्र' जारी किया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री तेमजेन इम्ना और अन्य भाजपा नेता भी उपस्थित रहे।

इस अवसर पर संबोधित करते हुए श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि नागालैंड के 'दृष्टि पत्र 2023' में कई मुद्दों का ध्यान रखा गया है और यह 'अष्टलक्ष्मी' का प्रतिनिधित्व करता है। 'दृष्टि पत्र' में शांति, बिजली, पर्यटन, 5जी कनेक्टिविटी, संस्कृति, प्राकृतिक खेती, खेल और क्षमता निर्माण को संबोधित किया गया है, जो यह स्पष्ट करता है कि आने वाले दिनों में एनडीपीपी और भाजपा गठबंधन नागालैंड में क्या करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज नागालैंड शांति, समृद्धि, विकास और मजबूती के रास्ते पर है।

श्री नड्डा ने कहा कि पार्टी का 'दृष्टि पत्र 2023' नागालैंड के लोगों की महत्वाकांक्षाओं, इच्छाओं और आकांक्षाओं को दर्शाता है।

'दृष्टि पत्र 2023' में भाजपा ने कई वादे किए हैं, जिन्हें अगले पांच साल के शासन में पूरा किया जाएगा।

'दृष्टि पत्र 2023' के प्रमुख बिंदुः

समृद्ध नागा पहचान और संस्कृति का संरक्षण

- हम सभी समुदायों की भाषाओं और संस्कृति के अनुसंधान एवं संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपये के निवेश से एक समर्पित 'नागालैंड सांस्कृतिक अनुसंधान कोष' स्थापित करेंगे।
- 500 करोड़ रुपये के निवेश से किफिरे में सारामती सांस्कृतिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जो ज्ञान संवर्धन और अनुसंधान पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा।

कृषि और किसान कल्याण

- हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय सहायता को मौजूदा 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये प्रति वर्ष करेंगे।
- हम संग्रह और प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों के समग्र कृषि-बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए 500 करोड़ रुपये के निवेश के साथ कृषि-बुनियादी ढांचा मिशन शुरू करेंगे।

महिला कल्याण

- नीदोनुओ अंगामी महिला कल्याण योजना की शुरुआत करेंगे, जिसके तहत लड़की के जन्म पर 50,000 रुपये का बांड दिया जाएगा।
- हम केजी से पीजी तक की सभी छात्राओं को निःशुल्क, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे।
- हम हर साल सभी उज्ज्वला लाभार्थियों को 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर मुहैया कराएंगे।
- कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी उपलब्ध कराने के लिए सीएम फ्री स्कूटी योजना की शुरुआत करेंगे।

युवा सशक्तीकरण

- सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, कृषि प्रसंस्करण, कपड़ा, एमएसएमई, पर्यटन आदि की स्थापना के माध्यम से अगले 5 वर्षों में 2 लाख स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।
- युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए नागालैंड कौशल विकास विश्वविद्यालय शुरू करने के लिए 500 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
- हम 10वीं और 12वीं कक्षा के सभी मेधावी छात्रों को डिजिटल टैबलेट उपलब्ध कराएंगे।
- हम एक राज्य खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे।

हेल्थकेयर को बढ़ावा देना

- हम 'आयुष्मान भारत योजना' के तहत प्रति परिवार वार्षिक बीमा सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करेंगे।
- हम सभी सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या को दोगुना करने और राज्य में डे-केयर क्लीनिकों की उपस्थिति का विस्तार करने के लिए 500 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे।
- हम नागालैंड राज्य कैंसर रोकथाम और उपचार नीति प्रस्तुत करेंगे और जुन्हेबोटो में एक सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए 400 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे।

पर्यटन को बढ़ावा

- हम 50,000 स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए नागालैंड पर्यटन कौशल मिशन शुरू करेंगे। ■

'ममता सरकार भ्रष्टाचार और घोटाले की जननी है'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 12 फरवरी, 2023 को पश्चिम बंगाल के पूर्बस्थली (पूर्बा बर्धमान) और पूर्बा मेदिनीपुर में आयोजित विशाल जनसभाओं को संबोधित किया और पश्चिम बंगाल की जनता से भ्रष्टाचारी, निरंकुश और अपराधियों को संरक्षित करनेवाली तृणमूल सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। उन्होंने राज्य की जनता से रक्तरंजित राजनीति को तिलांजलि देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जारी विकास यात्रा में भागीदार बनने का आह्वान किया। कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री सुकांता मजूमदार, सांसद एवं प्रभारी श्री पंकज चौधरी, सांसद श्रीमती लॉकेट चटर्जी, सांसद जगन्नाथ सरकार और सह प्रभारी श्री अमित मालवीय सहित कई वरिष्ठ नेता और पार्टी पदाधिकारी उपस्थित थे। पूर्बा मेदिनीपुर की जनसभा में केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी, श्री मंगल पांडेय सहित कई सांसद और पार्टी पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

श्री नड्डा ने कहा कि यह जनसैलाब बताता है कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन तय है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जंगलराज में शासन नाम की कोई चीज नहीं है, यहां तृणमूल का कुशासन है।

उन्होंने कहा कि 30 दिसंबर, 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पूज्य माताजी का स्वर्गवास हुआ था। उस दिन भी प्रधानमंत्री जी अपनी पूजनीया माताजी का अंतिम दर्शन करने के पश्चात् मां भारती की सेवा में जुट गए थे और यहां के विकास से जुड़े एक कार्यक्रम में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए शामिल होकर हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी तक चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। प्रधानमंत्रीजी ने तब पश्चिम बंगाल में लगभग 7800 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया था।

श्री नड्डा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में एसएससी घोटाला हुआ। टीईटी रिक्रूटमेंट में स्कैम हुआ, लॉटरी स्कैम हुआ। पहले सारदा, नारदा घोटाले हुए, चिटफंड घोटाला हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि ममता सरकार भ्रष्टाचार और घोटाले की जननी है। ममता दीदी पश्चिम बंगाल में रक्त रंजित राजनीति को प्रोत्साहित कर रही हैं। पश्चिम बंगाल की जनता अब संकल्प लेती है कि अत्याचार, गलत नीति, हिंसा अब और बर्दाश्त नहीं करेगी। बंगाल की जनता ने अब राज्य की बागडोर भाजपा के हाथों में सौंपने का मन बना लिया है। ■

'छत्तीसगढ़ का हित कमल निशान के साथ है'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 11 फरवरी, 2023 को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर (बस्तर) में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया और जनता से कांग्रेस की सरकार को उखाड़कर प्रदेश में एक बार पुनः पूर्ण बहुमत से विकास के प्रति समर्पित भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार बनाने की अपील की। कार्यक्रम में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री अरुण साव, छत्तीसगढ के प्रभारी श्री नितिन नवीन, छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री नारायण चंदेल, सांसद श्री संतोष पांडेय, प्रदेश के भाजपा महामंत्री श्री केदार कश्यप एवं पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. के.के. शर्मा सहित पार्टी के कई विधायक एवं वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारी उपस्थित थे।

श्री नड्डा ने कहा कि हाल के दिनों में छत्तीसगढ़ में तीन भाजपा नेताओं की निर्दयता से हत्या कर दी गई है। इस घटना ने मन को दुखित कर दिया है। हम सब नक्सलवाद के खिलाफ इस लड़ाई में आपके साथ खड़े हैं और लोकतांत्रिक तरीके से मजबूती के साथ इस विचारधारा से लड़ेंगे। भाजपा की डॉ. रमन सिंह सरकार में छत्तीसगढ़ में शांति थी, समृद्धि थी, लोगों के विकास के लिए काम हो रहा था लेकिन कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार में हत्याएं बढ़ गई हैं। ये काफी चिंता की बात है।

उन्होंने कहा कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्यायजी की पुण्यतिथि है। उन्होंने अंत्योदय और एकात्म मानववाद की दृष्टि दी थी। हमें ख़ुशी है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी इसी मंत्र को लेकर 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस पर जोरदार प्रहार करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का दूसरा नाम ही छल है। कांग्रेस का काम ही अटकाना, लटकाना और भटकाना है। कांग्रेस के नेता लोगों को भटकाते हैं, हम सबके विकास के लिए काम करते हैं।

श्री नड्डा ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि आप लोगों को बताइये कि हमारा हित कमल निशान के साथ है, छत्तीसगढ़ का हित कमल निशान के साथ है, किसानों का हित कमल निशान के साथ है, युवाओं की आकांक्षाओं को उड़ान देने का हित कमल निशान के साथ है, महिलाओं का सशक्तीकरण कमल निशान के साथ है और नक्सलियों से लड़ने का दम और ताकत भी भाजपा के ही पास है। ■

हमें पराक्रम की पराकाष्ठा करनी है : अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह ने 19 फरवरी, 2023 को महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा कार्यालय, कोल्हापुर में आयोजित 'विजय संकल्प रैली' को संबोधित किया। इसमें 12 विधानसभाओं से भाजपा के बूथ और शक्ति केंद्र के सभी कार्यकर्ता आये थे। साथ ही, कोल्हापुर और आसपास के संसदीय क्षेत्रों से भाजपा के सांसद, विधायक भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर बावनकुले, महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फड़णवीस, पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री चंद्रकांत पाटिल, राज्य सभा सांसद श्री धनंजय महादिक, कोल्हापुर से भाजपा सांसद संजय मांडलिक, पार्टी के राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री श्री शिव प्रकाश भी उपस्थित थे।

श्री शाह ने कहा कि मैं 2024 में भाजपा के संपूर्ण विजय अभियान के लक्ष्य के साथ आज यहां आया हूं। 2024 का चुनाव भाजपा - शिवसेना साथ में मिलकर लड़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बीते 9 वर्षों में देश में हर क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। प्रधानमंत्रीजी ने देश की प्रगति, सुरक्षा, शांति और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत की है, इसलिए हमारे खिलाफ सभी लोग इकट्ठे आने वाले हैं, लेकिन मैं किंचित भी इससे चिंतित नहीं हूं क्योंकि जिस पार्टी के पास आप जैसे देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं की टीम हो, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता।

श्री शाह ने कहा कि गत चुनाव में भाजपा - शिव सेना गठबंधन को लोकसभा की 48 में से 42 सीटों पर जीत मिली थी। हमें इस बार बहुमत नहीं बल्कि संपूर्ण विजय चाहिए। भाजपा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में महान भारत और समृद्ध भारत की रचना का लक्ष्य लेकर चली है। जब 2047 में भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे कर रहा होगा, तब हर क्षेत्र में भारत सर्वप्रथम हो, इस लक्ष्य की नींव हमें अभी डालनी है। भाजपा के हम सभी कार्यकर्ताओं को एक और बार पराक्रम की पराकाष्ठा करनी है और पुरुषार्थ कर महाराष्ट्र में जनता के आशीर्वाद से भाजपा - शिव सेना युति को संपूर्ण विजय दिलानी है, ताकि भारत विश्वगुरु के रूप में दुनिया में प्रतिष्ठित हो सके। ■

'हमारा लक्ष्य है नागालैंड की समस्या का सम्पूर्ण समाधान हो'

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह ने 20 फरवरी, 2023 को नागालैंड के मोन टाउन में आयोजित भाजपा-एनडीपीपी की संयुक्त विशाल जनसभा को संबोधित किया और जनता से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एक बार पुनः डबल इंजनवाली भाजपा-एनडीपीपी की विकासोन्मुखी सरकार बनाने की अपील की। कार्यक्रम में नागालैंड के

मुख्यमंत्री श्री नेफ्यू रियो, राज्य सभा सांसद श्रीमती फान्गनॉन कोन्याक, चुनाव बहिष्कार को वापस लेकर डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्ट्रेंथ करने वाले ईस्टर्न नगालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन (ENPO) के अध्यक्ष श्री संगताम, कोनयाक यूनियन के अध्यक्ष श्री तिंगथोक कोनयाक, पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री और नॉर्थ-ईस्ट के भाजपा सह-प्रभारी श्री ऋतुराज सिन्हा, नागालैंड के प्रभारी और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री नलिन कोहली सहित 9 विधानसभाओं से भारी संख्या में लोग उपस्थित थे।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने समग्र नॉर्थ-ईस्ट में शांति और विकास के एक नए युग की शुरुआत की है। हमने ब्रू-रियांग से समझौता किया, सालों पुराने बोडो समस्या का समाधान किया और कार्बी-ओंग्लोंग का शांति समझौता किया। मैं समग्र नागालैंड की जनता को कहना चाहता हूं कि हमारा लक्ष्य है नागालैंड की शांति वार्ता सफल हो और वर्षों पुरानी नागालैंड की समस्या का सम्पूर्ण समाधान हो।

उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद नागालैंड के मुख्यमंत्री श्री नेफ्यू रियो के नेतृत्व में बनने वाली एनडीए की सरकार आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेगी। चाहे वह बजटरी प्रोविजन के संबंध में हो, चाहे यहां के काउंसिल को अधिक अधिकार देना हो या नागालैंड के विकास में सबकी बराबर हिस्सेदारी की बात हो- इन सभी समस्याओं का समाधान भाजपा-एनडीपीपी की सरकार करेगी। श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे नार्थ-ईस्ट में मार्जिनलाइज्ड हो चुकी है। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को कहीं पर भी सफलता नहीं मिल रही है।

श्री शाह ने कहा कि मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आप भाजपा-एनडीपीपी के यहां के सभी 9 उम्मीदवारों को विजयी बनायें और राज्य में एक बार पुनः प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन वाली सरकार बनायें। ■

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली-दौसा-लालसोट खंड राष्ट्र को समर्पित

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 12 फरवरी को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का 246 किलोमीटर लंबा दिल्ली-दौसा-लालसोट खंड राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने 5,940 करोड़ रुपये से भी अधिक की लागत से विकसित होने वाली 247 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के प्रथम चरण को राष्ट्र को समर्पित करने पर गर्व व्यक्त किया।

राजस्थान में राजमार्गों के निर्माण के लिए 50,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों से केंद्र सरकार भी अवसंरचना में लगातार भारी निवेश कर रही है। उन्होंने कहा कि इस साल के बजट में अवसंरचना के लिए 10 लाख करोड़ रुपये आवंटित किये गए है, जो 2014 के आवंटन से 5 गुना ज्यादा है। उन्होंने इस तथ्य को रेखांकित किया कि इन निवेशों से राजस्थान के गरीब और मध्यम वर्ग को काफी फायदा होगा। ■

एक नजर में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के 246 किलोमीटर लंबे दिल्ली-दौसा-लालसोट खंड को 12,150 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। इस खंड के चालू होने से दिल्ली से जयपुर की यात्रा का समय 5 घंटे से घटकर लगभग 3.5 घंटे रह जाएगा और इससे पूरे क्षेत्र के आर्थिक विकास को अत्यधिक बढ़ावा मिलेगा।

दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 1,386 किमी की लंबाई के साथ भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। यह दिल्ली और मुंबई के बीच यात्रा की दूरी को 1,424 किमी से 12 प्रतिशत कम करके 1,242 किमी कर देगा और यात्रा का समय 24 घंटे से घटकर 12 घंटे तक यानी 50 प्रतिशत कम हो जाएगा। यह छह राज्यों— दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा और कोटा, इंदौर, जयपुर, भोपाल, वडोदरा और सूरत जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ेगा।

एक्सप्रेसवे 93 पीएम गति शक्ति आर्थिक नोड्स, 13 बंदरगाहों, 8 प्रमुख हवाई अड्डों और 8 मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क के साथ-साथ जेवर हवाई अड्डे, नवी मुंबई हवाई अड्डे और जेएनपीटी बंदरगाह जैसे नए आगामी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को भी सेवा प्रदान करेगा। ■

भारत 8 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त कर सकता है: विश्व बैंक अध्यक्ष

विश्व बैंक के अध्यक्ष श्री डेविड मॉलपास ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान भारत को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने मजबूत वापसी की। एक मजबूत निजी क्षेत्र, भूमि व कृषि सुधारों, छोटे उद्यमों को क्रेडिट सुनिश्चित कर तथा अन्य उपायों से भारत 8% की वृद्धि दर प्राप्त कर सकता है।

उन्होंने एक साक्षात्कार में ईटी को बताया कि आपूर्ति श्रृंखलाओं और विनिर्माण के वैश्विक विविधीकरण के बीच यह भारत के लिए निवेश को आकर्षित करने का सही समय है। उन्होंने देश को प्रतिस्पर्धी बनाने पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया। श्री मॉलपास जी20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से 22 फरवरी, 2023 को मुलाकात की। ■

एयर इंडिया ने फ्रांस और अमेरिका से 470 विमान खरीदने का किया ऐतिहासिक समझौता

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 14 फरवरी को एयर इंडिया और एयरबस के बीच साझेदारी के शुभारंभ के अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुएल मैक्रॉन, श्री रतन टाटा, चेयरमैन एमेरिटस, टाटा संस, श्री एन. चंद्रशेखरन, बोर्ड के अध्यक्ष, टाटा संस, श्री कैंपबेल विल्सन, सीईओ, एयर इंडिया और श्री गिलाउमे फाउरी, सीईओ एयरबस के साथ एक वीडियो कॉल वार्ता में भाग लिया।

गौरतलब है कि भारत की एयर इंडिया ने दुनिया में विमानन क्षेत्र का अब तक का सबसे बड़ा समझौता किया है। इसने एयरबस से 250 विमान और बोइंग से 220 विमान के साथ कुल 470 विमानों का ऑर्डर दिया है।

एयर इंडिया और एयरबस ने एयर इंडिया को 250 विमान, 210 सिंगल-आइज़ल ए320नियोस और 40 वाइडबॉडी ए350एस की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।

उड्डयन क्षेत्र की इन दो अग्रणी कंपनियों के बीच यह व्यावसायिक साझेदारी भारत-फ्रांस सामरिक साझेदारी की क्षमता को भी प्रदर्शित करती है और इस वर्ष अपनी 25वीं वर्षगांठ का प्रतीक है।

भारत में फ्रांसीसी कंपनियों की मजबूत उपस्थिति की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने फ्रांसीसी एयरोस्पेस इंजन निर्माता सफरान द्वारा भारतीय और अंतरराष्ट्रीय वाहक दोनों के लिए विमान इंजनों की सेवा के लिए भारत में अपनी सबसे बड़ी एमआरओ सुविधा स्थापित करने के हालिया निर्णय को भी याद किया। ■

अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐतिहासिक समझौते की घोषणा की

एक अन्य समझौते में अमेरिकी राष्ट्रपति श्री जो बाइडेन ने 14 फरवरी को भारत की एयर इंडिया और अमेरिकी विमानन कंपनी बोइंग के बीच 220 विमान खरीदने के एक ऐतिहासिक समझौते की घोषणा की। श्री बाइडेन ने इस समझौते को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि मुझे आज एअर इंडिया और बोइंग के बीच हुए समझौते और खरीद की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है। श्री बाइडेन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर वे भारत और अमेरिका के बीच के संबंध को और गहरा करने की उम्मीद कर रहे हैं। इस सौदे के जरिए इस दिशा में कदम उठाए गए हैं।

ई-संजीवनी ने 10 करोड़ लाभार्थियों को प्रदान की टेली-परामर्श सेवाएं

संजीवनी लाभार्थियों में 57% से अधिक महिलाएं हैं; लगभग 12% लाभार्थी वरिष्ठ नागरिक हैं; एक दिन में 5 लाख से अधिक रोगियों को टेली-परामर्श सेवाएं प्रदान की गईं

ई-संजीवनी देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक क्रांति है। भारत ने अपनी ई-हेल्थ यात्रा में एक ऐतिहासिक स्तर पार कर लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 16 फरवरी को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार भारत सरकार के राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म ई-संजीवनी ने 10 करोड़ लाभार्थियों को टेली-परामर्श सेवाएं प्रदान करके एक और ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ई-संजीवनी एप्प पर अभूतपूर्व रूप से 10 करोड़ टेली-परामर्श होने का स्वागत किया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया का एक ट्वीट साझा करते हुये प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि 10,00,00,000 टेली-परामर्श एक उल्लेखनीय कारनामा है। मैं उन सभी चिकित्सकों की सराहना करता हूं, जो भारत में एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य इको-प्रणाली बनाने में अग्रणी हैं।

टेली-परामर्श के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की सराहना करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि 15,731 मुख्य केंद्रों से 1,152 ऑनलाइन ओपीडी के माध्यम से 115,234 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (प्रतिनिधि केंद्रों के रूप में) में 10.011 करोड़ रोगियों को सेवा प्रदान की गई, जिसमें टेलीमेडिसिन में प्रशिक्षित 229,057 मेडिकल स्पेशलिस्ट और सुपर- स्पेशलिस्ट शामिल थे। ई-संजीवनी को एक दिन में 10 लाख से अधिक परामर्श देने के लिए आगे और संवर्धित किया गया है, अब तक मंच एक दिन में 5,10,702 रोगियों की सेवा करने का अपना उच्चतम स्तर हासिल कर चुका है।

'ई-संजीवनी' भारत की राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में दुनिया की सबसे बड़ी टेलीमेडिसिन सेवा है। ई-संजीवनी विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए एक वरदान साबित हुई है, जहां स्वास्थ्य सुविधा तक पहुंच कठिन थी। इसके बाद से इसे स्वास्थ्य से जुड़े सभी क्षेत्रों में व्यापक रूप से लागू किया गया है और इसने हमारे देश में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को बदल दिया है।

यह ध्यान देने योग्य बात है कि ई-संजीवनी के 57% से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं और लगभग 12% लाभार्थी वरिष्ठ नागरिक हैं। इससे यह भी पता चलता है कि मंच आबादी के सबसे असुरक्षित वर्गों में अपनी पहुंच बना रहा है, जहां इसके प्रभाव का अधिकतम असर दिखता है। ■

लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (एसएसएलवी) का सफल प्रक्षेपण

इस सफल प्रक्षेपण के साथ भारत को एक नया प्रक्षेपण यान मिला है, जिसका उद्देश्य उद्योग के माध्यम से मांग के आधार पर प्रक्षेपित छोटे उपग्रहों का व्यावसायीकरण करना था

गत 10 फरवरी को लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (एसएसएलवी) ने तीन उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। अपनी दूसरी विकासात्मक उड़ान के तहत एसएसएलवी-डी2 यान ने ईओएस-07, जानुस-1 और आजादीसैट-2 उपग्रहों को 37 डिग्री के झुकाव के साथ उनकी लक्षित 450 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में स्थापित किया। इसने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले प्रक्षेपण स्थल से अपनी 15 मिनट की उड़ान के बाद इसने तीनों उपग्रहों को उनकी कक्षा में स्थापित कर दिया।

एसएसएलवी 'मांग पर प्रक्षेपण' आधार पर पृथ्वी की निचली कक्षाओं में 500 किलोग्राम तक के छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए इसरो द्वारा विकसित नया लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान है। इसे क्रमशः तीन ठोस चरणों 87 टन, 7.7 टन और 4.5 टन के साथ संरूपित किया गया है। एसएसएलवी एक 34 मीटर लंबा, 2 मीटर व्यास वाला यान है, जिसका उत्थापन द्रव्यमान 120 टन है।

एसएसएलवी छोटे, सूक्ष्म या नैनो उपग्रहों (10 से 500 किलोग्राम भार तक के) को 500 किलोमीटर की कक्षा में प्रक्षेपित करने में सक्षम है। यह कम लागत में अंतरिक्ष के लिए पहुंच, कम प्रतिवर्तन काल, कई उपग्रहों को समायोजित करने की सुविधा प्रदान करने के साथ न्यूनतम प्रक्षेपण अवसंरचना की मांग करता है।

एसएसएलवी-डी2 ने जिन तीन उपग्रहों को प्रक्षेपित किया, उनमें ईओएस-07 इसरो द्वारा तैयार किया गया 153.6 किलोग्राम का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। वहीं, जानुस-1, अमेरिकी कंपनी अंतारिस का 10.2 किलोग्राम वजन का एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन उपग्रह है। आजादी सैट-2, एक 8.8 किलोग्राम वजन का उपग्रह है, जिसे स्पेस किड्ज इंडिया ने पूरे भारत में 750 छात्राओं द्वारा विकसित विभिन्न वैज्ञानिक पेलोड को एकीकृत करके तैयार किया है।

आज के सफल प्रक्षेपण के साथ भारत को एक नया प्रक्षेपण यान मिला है, जिसका उद्देश्य उद्योग के माध्यम से मांग के आधार पर प्रक्षेपित छोटे उपग्रहों का व्यावसायीकरण करना था। इसरो अंतरिक्ष में लघु उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की बढ़ती वैश्विक जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। ■

वित्तीय वर्ष 2022-23 में अब तक प्रत्यक्ष कर संग्रह 24.09 प्रतिशत बढ़कर 15.67 लाख करोड़ रुपये रहा

प्रत्यक्ष कर संग्रह, रिफंड का शुद्ध 12.98 लाख करोड़ रुपये है जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के शुद्ध संग्रह से 18.40% अधिक है

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार प्रत्यक्ष कर संग्रह के अस्थायी आंकड़ों में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। 10 फरवरी, 2023 तक प्रत्यक्ष कर संग्रह दर्शाता है कि सकल संग्रह 15.67 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के सकल संग्रह से 24.09% अधिक है। प्रत्यक्ष कर संग्रह, रिफंड का शुद्ध 12.98 लाख करोड़ रुपये है जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के शुद्ध संग्रह से 18.40% अधिक है। यह संग्रह वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रत्यक्ष करों के कुल बजट अनुमानों का 91.39% है और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रत्यक्ष करों के संशोधित अनुमानों का 78.65% है।

जहां तक सकल राजस्व संग्रह के संदर्भ में कॉर्पोरेट आयकर (सीआईटी) और व्यक्तिगत आयकर (पीआईटी) की वृद्धि दर का संबंध है, सीआईटी के लिए विकास दर 19.33% है जबकि पीआईटी (एसटीटी सहित) के लिए 29.63% है। रिफंड के समायोजन के बाद सीआईटी संग्रह में शुद्ध वृद्धि 15.84% है और पीआईटी संग्रह में 21.93% (केवल पीआईटी)/21.23% (एसटीटी सहित पीआईटी) है।

1 अप्रैल, 2022 से 10 फरवरी, 2023 के दौरान 2.69 लाख करोड़ रुपये की राशि का रिफंड जारी किया गया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान जारी किए गए रिफंड से 61.58% अधिक है। ■

14वें एयरो इंडिया के बंधन समारोह में करीब 80,000 करोड़ रुपये की हुईं 266 साझेदारियां

हेलीकॉप्टर इंजनों के डिजाइन, विकास, निर्माण और आजीवन समर्थन के लिए संयुक्त उद्यम के गठन के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और फ्रांस के सफरन हेलीकॉप्टर इंजन के बीच वर्क शेयर के लिए समझौता ज्ञापन पर किए गए हस्ताक्षर

रक्षा मंत्रालय द्वारा 15 फरवरी को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार बेंगलुरु में हुए 14वें एयरो इंडिया के बंधन समारोह में 201 समझौता ज्ञापनों, 53 प्रमुख घोषणाओं, नौ उत्पादों का शुभारंभ और तीन प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण सहित लगभग 80,000 करोड़ रुपये सहित 266 साझेदारियां हुईं।

प्रमुख समझौते व उत्पाद निम्न हैं:

प्रमुख समझौते

- हेलीकॉप्टर इंजनों के डिजाइन, विकास, निर्माण और आजीवन समर्थन के लिए संयुक्त उद्यम के गठन के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और फ्रांस के सफरन हेलीकॉप्टर इंजन के बीच वर्क शेयर के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान के लिए आईडबल्यूबीसी और अन्य एलआरयूएस पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और वैमानिकी विकास एजेंसी के बीच समझौता ज्ञापन हुआ।
- बीएसएस मटेरियल लिमिटेड और एडीयूएसईए इंक. डिवीजन (यूएसए) की एक कंपनी पेगासस इंजीनियरिंग के बीच भारतीय सेना के लिए लॉजिस्टिक ड्रोन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में अग्रिम चौकियों पर तैनात सैनिकों के लिए तेज़ हवा/झोंके की स्थिति, बारिश/हिमपात आदि में ऑपरेशन की क्षमता के साथ अंतिम मील डिलीवरी के लिए सहयोग किया गया।
- भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और बुल्गारिया के बल्टेक्सप्रो लिमिटेड के बीच भारत में 122 मिली मीटर जीआरएडी बीएम ईआर और एनओएनईआर रॉकेट के लिए विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने और आवश्यकताओं के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टीओटी सहित) को पूरा करने के लिए समझौता ज्ञापन।
- भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के फास्ट अटैक क्राफ्ट पोत के लिए स्वदेशी सामग्री का समर्थन करने के लिए एमएमटीयू 16वी4000एम73एल इंजन के स्थानीयकरण के साथ लाइसेंस उत्पादन के लिए जीआरएसई और रोल्स-रॉयस सॉल्यूशंस जीएमबीएच के बीच समझौता ज्ञापन।
- बीईएमएल ने टी-72/टी-90 टैंकों के लिए ट्रावेल असेंबली के विकास और आपूर्ति के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन-डीआरडीओ के आर एंड डीईई के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टीओटी) के लिए लाइसेंस समझौता किया।
- भारतीय प्लेटफार्मों के लिए समुद्री गश्ती रडार में भविष्य के व्यापार पर सहयोग के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और इज़राइल के एल्टा सिस्टम्स लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन।

मुख्य उत्पाद

- **कम दूरी की ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल (भारत डायनेमिक्स लिमिटेड) की बड़े पैमाने पर शुरुआत:** वीएलएसआरएसएएम एक अगली पीढ़ी, जहाज-आधारित, सभी मौसम, वायु रक्षा हथियार है, जिसका उपयोग नौसेना द्वारा सुपरसोनिक समुद्री स्किमिंग जैसे विमान और यूएवी लक्ष्य खिलाफ त्वरित प्रतिक्रिया बिंदु रक्षा के रूप में किया जा सकता है। मिसाइल में सभी मौसम की क्षमता के साथ धुआं रहित प्रणोदन प्रणाली है। इसमें अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक काउंटर-काउंटर उपाय सुविधाओं के साथ अत्यधिक चुस्त कॉन्फ़िगरेशन है।
- **बीएमपी II (भारत डायनेमिक्स लिमिटेड) के लिए एसएएल सीकर एटीजीएम:** बीएमपी-II के लिए सेमी-एक्टिव लेजर सीकर आधारित एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल 4,000 मीटर की रेंज और 25 सेकंड के उड़ान समय के साथ एक सबसोनिक मिसाइल है। प्रक्षेपण के साथ मिसाइल का वजन 23 किलोग्राम है। इसका उपयोग ट्यूब और टैंक और इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स जैसे चलते हुए और स्थिर लक्ष्यों को अक्षम करने के लिए विभिन्न प्रकार के इलाकों में किया जा सकता है।
- रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन-डीआरडीओ (एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड) की तकनीक पर आधारित स्वदेशी निर्मित 'काउंटर ड्रोन रडार'। ■

मोदी स्टोरी

ताना-रीरी : नरेन्द्र मोदी ने कैसे पूरा किया बचपन का सपना

–दशरथ पटेल

वडनगर का ताना-रीरी मंदिर अब आस-पास के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के एक परित्यक्त मंदिर के जीर्णोद्धार और विकास के प्रयासों ने ताना-रीरी मंदिर को न केवल आकर्षण का केंद्र बनाया, बल्कि उनके बचपन के सपने को साकार किया। आइए जानते हैं कैसे?

श्री दशरथ पटेल श्री नरेन्द्र मोदी के बचपन के मित्र हैं। दोनों अपने छात्र जीवन के दौरान स्कूल से कॉलेज तक साथ रहे। वह याद करते हैं, जब वे एम.एन. कॉलेज, विसनगर, गुजरात में पढ़ रहे थे, तब वे दोनों ताना-रीरी मंदिर गए थे।

उस समय मंदिर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में था। प्लास्टर उखड़ गया था, दीवार से ईंटें भी निकली हुई थीं। मंदिर की सुध लेने वाला कोई नहीं था।

मंदिर की दयनीय स्थिति को देखते हुए श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने मित्र से कहा कि जब वह वापस आएंगे, तो मंदिर की मरम्मत कराएंगे। उस समय श्री दशरथ पटेल को इस बात पर थोड़ा संदेह हुआ, क्योंकि छात्र जीवन में फिर से मंदिर जाना काफी कठिन था। उन्होंने श्री नरेन्द्र मोदी से अपनी बात रखते हुए कहा कि शायद हमें दोबारा यहां आने का समय न मिले। तब नरेन्द्र मोदी ने उन्हें जवाब दिया, "मंदिर का जीर्णोद्धार सही समय पर होगा।"

श्री पटेल आगे कहते हैं कि कई वर्षों के बाद जब श्री नरेन्द्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने ताना-रीरी मंदिर के दर्शन किए। श्री मोदी ने मंदिर के जीर्णोद्धार और इसे एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण के रूप में विकसित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जहां श्रद्धालु आसानी से आ सकें।

उन्होंने देश के कुछ प्रमुख गायकों को आमंत्रित करके वार्षिक ताना-रीरी संगीत समारोह को एक राष्ट्रीय कार्यक्रम भी बनाया। इससे लोगों को मंदिर और उसके ऐतिहासिक महत्व के बारे में पता चला।

श्री पटेल का कहना है कि श्री नरेन्द्र मोदी ने ताना-रीरी मंदिर के जीर्णोद्धार का बचपन का संकल्प पूरा किया। उन्होंने न केवल अपने संकल्प को पूरा किया, बल्कि संगीत समारोह के माध्यम से इस स्थान को उचित महत्व भी दिया। अब, यह एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है जहां दुनिया के विभिन्न हिस्सों से लोग आते हैं और दर्शन करते हैं। ■

कमल पुष्प

सेवा, समर्पण, त्याग, संघर्ष एवं बलिदान

गरियाबंद से देवभोग तक उन्होंने संगठन को मजबूत किया

श्री प्रेमलाल सिन्हा बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे। संघ की विचारधारा से जुड़े होने के कारण उन्हें कांग्रेस सरकार ने प्रताड़ित किया। शासकीय सेवा में शिक्षक रहते हुए संस्था का कार्य कठिन था, अतः 1960 में उन्होंने विद्यालय के पद से त्यागपत्र दे दिया और भारतीय जनसंघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गये। संगठन के प्रति अपनी निष्ठा और कर्तव्यनिष्ठा के कारण कांग्रेसियों के दबाव के आगे वे कभी नहीं झुके। जीविकोपार्जन के लिए उन्होंने साइकिल पंक्चर की दुकान खोली और आर्थिक तंगी में भी वह अपने पथ पर अडिग रहे। उन्होंने गरियाबंद से देवभोग तक लगातार संगठन को मजबूत करने के लिए भ्रमण किया। यहां तक कि 1975 में आपातकाल के दौर में उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उनकी पहचान एक शानदार वक्ता, एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में थी और उन्होंने भाजपा में भी अपने विभिन्न दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन किया। ■

प्रेमलाल सिन्हा

जन्म	: 17 अक्टूबर, 1937
सक्रिय वर्ष	: 1960-1998
स्थान	: छत्तीसगढ़
जिला	: गरियाबंद

भाजपा के वरिष्ठ नेता और गुजरात के पूर्व राज्यपाल ओमप्रकाश कोहली का निधन

भाजपा के वरिष्ठ नेता और गुजरात के पूर्व राज्यपाल श्री ओम प्रकाश कोहली का 20 फरवरी को नोएडा में बीमारी के बाद निधन हो गया। वह 87 वर्ष के थे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, "श्री ओपी कोहली जी के निधन से दुःखी हूं। उन्होंने दिल्ली में हमारी पार्टी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। सांसद और राज्यपाल के रूप में उन्होंने लोक कल्याण के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। शिक्षा के क्षेत्र में भी उनकी गहरी दिलचस्पी थी। मेरी संवेदना परिवार के साथ है।"

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, "भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, गुजरात के पूर्व राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। संगठन निर्माण, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पण व समाज के लिए आपका सेवाभाव सदैव अनुकरणीय रहेंगे। ईश्वर दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान दें।"

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने श्री कोहली के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, "गुजरात व मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ भाजपा नेता ओम प्रकाश कोहली जी के निधन का दुःखद समाचार मिला। कोहली जी का जीवन एक शिक्षक, कार्यकर्ता व प्रशासक के तौर पर सभी को प्रेरित करने वाला रहा। दुःख की इस घड़ी में उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं।"

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा, "श्री ओपी कोहलीजी ने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में अपनी कार्य-क्षमता और विद्वता के कारण काफ़ी सम्मान अर्जित किया। वे गुजरात के राज्यपाल रहे और दिल्ली में भाजपा को मज़बूत करने में भी उनकी प्रभावी भूमिका रही। उनके निधन से मुझे गहरा दुःख हुआ है। ईश्वर उनके परिवार को संबल प्रदान करे।"

दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष श्री कोहली पिछले दो तीन महीनों से अस्वस्थ थे। उनका अंतिम संस्कार 21 फरवरी को निगम बोध घाट पर किया गया।

श्री कोहली 2014 और 2019 के बीच गुजरात के 19वें राज्यपाल रहे। उन्होंने 2016 से 2018 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल और 2014 में तीन सप्ताह के लिए गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला। श्री कोहली ने भाजपा केंद्रीय कार्यालय सचिव, संसदीय दल कार्यालय सचिव और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष के दायित्व का भी निर्वहन किया। ■

'छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान नक्सली हमले बढ़े हैं'

छत्तीसगढ़ में तीन भाजपा नेताओं की निर्दयतापूर्वक हत्या, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दी श्रद्धांजलि

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 11 फरवरी, 2023 को नारायणपुर पहुंचकर जिला भाजपा कार्यालय में भाजपा के दिवंगत नेता सागर साहू के पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें नमन करते हुए उनके कृतित्व को याद किया। श्री नड्डा ने स्वर्गीय श्री सागर साहू के पार्थिव शरीर पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा ओढ़ाकर उन्हें सम्मान दिया। श्री नड्डा ने संदेश दिया कि भाजपा परिवार पूरी तरह से इस घड़ी में श्री सागर साहू के परिजनों के साथ खड़ा है।

श्री नड्डा ने दिवंगत भाजपा नेता के परिजनों से भी मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दिया। इस दौरान उनके साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री अरुण साव भी उपस्थित रहे। ज्ञात हो कि 10 फरवरी को नारायणपुर के भाजपा जिला उपाध्यक्ष श्री सागर साहू की नक्सलियों ने उनके घर में घुस कर निर्दयता से हत्या कर दी थी। श्री सागर साहू 25 साल से भाजपा से जुड़े हुए थे।

भरे मन और दुःखी हृदय से भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कल नक्सलियों ने हमारे कर्मठ नेता श्री सागर साहू जी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। जैसे ही मुझे पता चला, मैंने निश्चय किया कि मैं उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धा–सुमन अर्पित करने और उनके परिजनों से मिलने जरूर जाउंगा। मैं आज सागर साहू जी के परिजनों से कहना चाहता हूं कि भाजपा के सभी कार्यकर्ता असह्य दुःख की इस घड़ी में आपके साथ एकजुट होकर खड़े हैं। अपने कर्मठ सहयोगी के बिछड़ने का यह गम बहुत गहरा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान नक्सली हमले बराबर बढ़े हैं। हमारे नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों में हमारे तीन नेताओं की छत्तीसगढ़ में निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी गई है। कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार में हत्या की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं जो काफी चिंता की बात है। ■

प्रधानमंत्री ने दिल्ली स्थित मेजर ध्यान चंद राष्ट्रीय स्टेडियम में 'आदि महोत्सव' का किया उद्घाटन

'आजादी के अमृत महोत्सव में 'आदि महोत्सव' देश की आदि विरासत की भव्य प्रस्तुति कर रहा है'

देश अपने जनजातीय गौरव के संबंध में अभूतपूर्व गर्व के साथ आगे बढ़ रहा है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 16 फरवरी को दिल्ली स्थित मेजर ध्यान चंद राष्ट्रीय स्टेडियम में मेगा राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव, 'आदि महोत्सव' का उद्घाटन किया। 'आदि महोत्सव' राष्ट्रीय मंच पर जनजातीय संस्कृति को प्रदर्शित करने का एक प्रयास है। इसके तहत जनजातीय संस्कृति, शिल्प, खान-पान, वाणिज्य और पारंपरिक कला की भावना का उत्सव मनाया जाता है। यह जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ लिमिटेड (ट्राइफेड) की वार्षिक पहल है।

आयोजन-स्थल पर पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा को पुष्पांजलि अर्पित की और प्रदर्शनी में लगे स्टॉलों का अवलोकन किया।

उपस्थितजनों को सम्बोधित करते हुये श्री मोदी ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में 'आदि महोत्सव' देश की आदि विरासत की भव्य प्रस्तुति कर रहा है। उन्होंने भारत के जनजातीय समाजों की प्रतिष्ठित झांकियों को रेखांकित किया और विभिन्न रसों, रंगों, सजावटों, परंपराओं, कला और कला विधाओं, रसास्वादन और संगीत को जानने-देखने का अवसर मिलने पर हर्ष व्यक्त किया।

श्री मोदी ने कहा कि आदि महोत्सव कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होने वाली भारत की विविधता और शान का परिचायक है। उन्होंने कहा कि आदि महोत्सव अनन्त आकाश की तरह है, जहां भारत की विविधता इंद्रधनुष के रंगों की तरह दिखती है। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि आदि महोत्सव भारत की विविधता में एकता को शक्ति देता है तथा साथ में विरासत को मद्देनजर रखते हुये विकास के विचार को गति देता है।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि देश अपने जनजातीय गौरव के संबंध में अभूतपूर्व गर्व के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि वे जनजातीय उत्पादों को विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को पूरे गर्व के साथ उपहार में देते हैं। श्री मोदी ने जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने में सरकार के प्रयासों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि जनजातीय उत्पादों को अधिक से अधिक बाजार तक पहुंचना चाहिए और उनकी पहचान और मांग में वृद्धि होनी चाहिए।

'वन धन मिशन' के बारे में विस्तार से बताते हुए श्री मोदी ने बताया कि विभिन्न राज्यों में 3000 से अधिक वन धन केंद्र स्थापित किए गए हैं। लगभग 90 लघु वन उत्पादों को एमएसपी के दायरे में लाया गया है, जिनकी संख्या 2014 की संख्या से सात गुना अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि इसी तरह देश में स्व-सहायता समूहों के बढ़ते नेटवर्क से आदिवासी समाज लाभान्वित हो रहा है। देश में 80 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों में 1.25 करोड़ आदिवासी सदस्य कार्यरत हैं।

जनजातीय कलाओं और कौशल विकास को प्रोत्साहित कर रही है सरकार

श्री मोदी ने सरकार के प्रयासों पर जोर दिया, जो वह जनजातीय युवाओं को ध्यान में रखकर जनजातीय कलाओं और कौशल विकास को प्रोत्साहित कर रही है। इस वर्ष के बजट का उल्लेख करते हुये प्रधानमंत्री ने बताया कि 'पीएम विश्वकर्मा योजना' को पारंपरिक शिल्पकारों के लिये शुरू किया गया है, जहां कौशल विकास तथा अपने उत्पादों को बाजार में बेचने के लिये समर्थन देने के अलावा आर्थिक सहायता भी दी जायेगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जनजातीय बच्चे देश के किसी भी कोने में हों, उनकी शिक्षा मेरी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि 2000-2014 के बीच एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की संख्या 80 थी, जो पांच गुना बढ़ गई है तथा 2014 से 2022 के बीच उनकी संख्या 500 हो गई है। 400 से अधिक स्कूल शुरू हो चुके हैं, जहां लगभग 1 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। इस वर्ष के बजट में इन स्कूलों के लिये 38 हजार शिक्षकों और स्टाफ की घोषणा की गई है। जनजातीय छात्रों के लिये छात्रवृत्ति भी दुगनी कर दी गई है।

श्री मोदी ने इस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाये जाने का उल्लेख करते हुये कहा कि पोषक अनाज सदियों से जनजातीय खान-पान का हिस्सा रहे। उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों के भोजन के बारे में जागरूकता फैलाने पर बल दिया, क्योंकि इससे न केवल लोगों के स्वास्थ्य को लाभ मिलेगा, बल्कि जनजातीय किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। ■

'नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं को नई सदी के लिए तैयार करती है'

देशभर में अब तक 38 करोड़ मुद्रा ऋण दिये जा चुके हैं; लगभग आठ करोड़ युवा पहली बार उद्यमी बने हैं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 20 फरवरी को वीडियो संदेश के माध्यम से उत्तराखंड रोजगार मेले को सम्बोधित किया। उपस्थितजनों को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन उन लोगों के लिये नई शुरुआत का दिन है, जिन्हें अपने नियुक्त पत्र मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह न केवल जीवन को बदलने वाला अवसर है, बल्कि समग्र बदलाव के लिये एक माध्यम भी है।

शिक्षा क्षेत्र के संदर्भ में देश में होने वाले नये प्रयोगों को रेखांकित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि नियुक्ति पाने वाले लोगों में से ज्यादातर लोग शिक्षा क्षेत्र में सेवा देंगे। इस संकल्प को आगे बढ़ाने के क्रम में उत्तराखंड के युवाओं के कंधों पर आने वाली जिम्मेदारी का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति भारत के युवाओं को नई सदी के लिये तैयार कर रही है।

श्री मोदी ने कहा कि केंद्र और उत्तराखंड सरकार का सतत प्रयास है कि आगे बढ़ने के लिये सही माध्यम को सुगम्य बनाने के क्रम में हर युवा को उसकी रुचि के अनुसार नये अवसर मिलें। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवाओं में बहाली अभियान भी इसी दिशा में की जाने वाली पहल है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लाखों युवाओं को पिछले कुछ महीनों में केंद्र सरकार से नियुक्त पत्र मिले हैं और उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता भी व्यक्त कि उत्तराखंड इसका हिस्सा बन रहा है। श्री मोदी ने बताया कि ऐसे बहाली अभियान देशभर में भाजपाशासित प्रदेशों तथा केंद्रशासित प्रदेशों मे बड़े पैमाने पर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि आज उत्तराखंड भी इसका हिस्सा बन गया है।

श्री मोदी ने जोर देकर कहा हमें उस पुरानी धारणा को बदलना है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों में नये रोजगार और स्व-रोजगार अवसरों के सृजन को रेखांकित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार का यह सतत प्रयास है कि उत्तराखंड के युवा अपने गांव वापस आ सकें।

केंद्र और उत्तराखंड सरकार का सतत प्रयास है कि आगे बढ़ने के लिये सही माध्यम को सुगम्य बनाने के क्रम में हर युवा को उसकी रुचि के अनुसार नये अवसर मिलें

उत्तराखंड में अवसंरचना विकास में होने वाले निवेश पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नई सड़कों का निर्माण और रेल लाइनों के बिछाने से न केवल कनेक्टिविटी बढ़ रही है, बल्कि रोजगार के अनेक अवसर भी पैदा हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि हर जगह रोजगार के अवसर बढ़ाये जा रहे हैं। उन्होंने इस सिलिसले में निर्माण कामगारों, इंजीनियरों, कच्चे माल के उद्योगों और दुकानों का उदाहरण दिया।

श्री मोदी ने यह भी कहा कि परिवहन क्षेत्र में बढ़ती मांग के कारण नये अवसर पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों के युवाओं को रोजगार के लिये बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था, लेकिन आज हजारों युवा सामान्य सेवा केंद्रों में काम कर रहें तथा गांवों में इंटरनेट व डिजिटल सेवायें उपलब्ध करा रहे हैं।

उत्तराखंड में बढ़ रहा है पर्यटन क्षेत्र

प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि उत्तराखंड में पर्यटन क्षेत्र बढ़ रहा है, क्योंकि सुदूर क्षेत्रों को सड़क, रेल और इंटरनेट से जोड़ दिया गया है। श्री मोदी ने रेखांकित किया कि पर्यटन सेक्टर में रोजगार व स्व-रोजगार अवसरों के बढ़ने में मुद्रा योजना महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दुकानों, ढाबों, अतिथिगृहों और होमस्टे का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे कारोबारों के लिये बिना किसी जमानत के 10 लाख रुपये तक ऋण दिया जा रहा है।

श्री मोदी ने कहा कि देशभर में अब तक 38 करोड़ मुद्रा ऋण दिये जा चुके हैं; लगभग आठ करोड़ युवा पहली बार उद्यमी बने हैं। उन्होंने यह भी बताया कि महिलाओं और अजा/अजजा/ओबीसी वर्ग के युवाओं का हिस्सा इसमें अधिकतम है।

अपने सम्बोधन के समापन पर श्री मोदी ने कहा कि यह भारत के युवाओं के लिये अद्भुत संभावनाओं का 'अमृत काल' है। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी सेवाओं के जरिये भारत के विकास को गति दें। ■

मोदी सरकार में भारत की 'सॉफ्ट पावर' खिल रही है

इसी महीने भारत की उदार लेकिन रणनीतिक पहल उस वक्त फिर एक बार नजर आयी, जब भारत ने विनाशकारी भूकंप के बाद तुर्की की सहायता के लिए सबसे पहले अपना हाथ आगे बढ़ाया। हालांकि, यह बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है कि दोनों देशों के बीच जम्मू-कश्मीर और सीमा पार आतंकवाद को लेकर अक्सर वैश्विक मंचों पर तीखे आदान-प्रदान और वाद-विवाद होते रहे हैं, जिससे दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण रहे हैं

बैजयंत जय पांडा

हमारे प्रधानमंत्री ने 2014 से ही संघर्षों से परे देखने और बड़े हित की रक्षा के लिए उत्तम प्रयास करने की मंशा व्यक्त की है। प्रधानमंत्री की मंशा की झलक कोविड-19 महामारी, श्रीलंका के आर्थिक संकट और अब फिर से एक बार भूकंप प्रभावित तुर्की में दिखाई दी है। हालांकि, भविष्य में भारत और तुर्की के बीच आपसी संबंधों की भविष्यवाणी करना अभी जल्दबाजी होगी, फिर भी स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि भारत की मानवीय पहलों ने मित्रता के दरवाजे खोले हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जब 2014 में अपने पहले कार्यकाल के लिए पद और गोपनीयता की शपथ ली, उसके कुछ दिनों बाद ही दिल्ली का दौरा करने आये एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक ने कहा कि क्या वह संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत के संबंधों को प्राथमिकता नहीं देंगे। यह आशंका उस पीड़ा पर आधारित थी, जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री को उस देश के कुछ हलकों के कारण झेलनी पड़ी थी, जिसमें बनावटी तथ्यों के आधार पर कुछ समय के लिए उन्हें आगंतुक वीजा देने तक से इनकार करना भी शामिल था। हालांकि, भारत की न्यायपालिका ने हर स्तर पर इन तथ्यों को गलत साबित कर दिया है। उस राजनयिक की चिंता निराधार साबित हुई और प्रधानमंत्री ने उसी साल सितंबर में अमेरिका का दौरा किया, दोस्त बनाए और लोगों को प्रभावित किया।

प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में भारतीय डायस्पोरा के एक कार्यक्रम शामिल हुए। भारत ने इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने बढ़ते हुए दबदबे को विश्व मंच पर प्रदर्शित किया, जो दुनिया भर में अपनी तरह का अनोखा कार्यक्रम था।

अब इसी महीने भारत की उदार लेकिन रणनीतिक पहल उस वक्त फिर एक बार नजर आयी, जब भारत ने विनाशकारी भूकंप के बाद तुर्की की सहायता के लिए सबसे पहले अपना हाथ आगे बढ़ाया। हालांकि, यह बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है कि दोनों देशों के बीच जम्मू-कश्मीर और सीमा पार आतंकवाद को लेकर अक्सर वैश्विक मंचों पर तीखे आदान-प्रदान और वाद-विवाद होते रहे हैं, जिससे दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण रहे हैं।

छोटी-छोटी बातों और व्यक्तिगत अपमानों को एक तरफ रखकर संघर्षों से परे देखने और बड़े राष्ट्रीय एवं वैश्विक हित में सही दिशा में काम करने की इच्छाशक्ति दुर्लभ है और यह कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। यहां तक कि राजनेता और राजनयिक भी इंसान होते हैं और हमेशा ऊंचे मापदंड़ों को कायम रखने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। इसके लिए एक बड़ा दिल, दृढ़ संकल्प और उच्च सिद्धांत में गहरा विश्वास होना चाहिए। प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण 'वसुधैव कुटुम्बकम'- दुनिया एक परिवार के भारतीय दर्शन में समाविष्ट है।

पिछले नौ वर्षों में भारत ने संकटग्रस्त देशों की सहायता करने को लेकर अपने पहले के प्रयासों में उल्लेखनीय रूप से सुधार किया है। यह महामारी और उसके बाद के परिवेश में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गया है। दुनिया ने इस बात को भी विस्मयता के साथ देखा कि भारत ने कैसे भयानक भविष्यवाणियों को खारिज करते हुए, महामारी के दौरान अन्य देशों की तुलना में बेहतर काम किया। भारत ने स्वदेशी टीके विकसित किए और इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे तेज टीकाकरण अभियान शुरू किया। करोड़ों लोगों के टीकाकरण कार्यक्रम को चलाने के अलावा हमने 100 से अधिक देशों को कोविड वैक्सीन की करोड़ों खुराक भी उपलब्ध करवायी, जिसने दुनिया को भी चौंका दिया।

आर्थिक रूप से तबाह हो चुके पड़ोसियों को भारत द्वारा प्रदान की जाने वाली पर्याप्त वित्तीय सहायता एक प्रमुख मील का पत्थर साबित हुई। वैश्विक आर्थिक संकट के बीच पर्याप्त मात्रा, मैत्रीपूर्ण आउटरीच और भू-राजनीतिक संदर्भ में यह विशिष्ट हैं। उदाहरण के लिए श्रीलंका का मामले लें, श्रीलंका को भारतीय मदद तब मिली जब देश गंभीर संकट में था और अंतरराष्ट्रीय पुनर्भुगतान को करने में असमर्थ था। यह चीन के बिल्कुल विपरीत था, जिसके व्यापारिक क्रियाकलापों ने एक चमकीले द्वीप को आर्थिक पतन की ओर धकेल दिया था। यह भारत की तेजी से बढ़ती आर्थिक ताकत के कारण संभव हुआ है। यदि भारत के पास इन पहलों का समर्थन करने के साधन नहीं होते तो, केवल नेक इरादों के साथ भी भारत ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। भारतीय अर्थव्यवस्था

शेष पृष्ठ १६ पर...

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर का विकास

तरुण चुघ

आजादी का अमृतकाल चल रहा है। यह दुर्भाग्य की बात रही कि आजादी के बाद भारत में कांग्रेस की सरकारों द्वारा न तो पूर्वोत्तर के आर्थिक विकास के लिए ठोस जमीनी प्रयास किए गए और न ही वहां के नागरिकों को विकास की मुख्यधारा में ही जोड़ने के काम किये गए। इस वजह से इस हिस्से के प्रति शेष देश में सहज अपनत्व की भावना उस ढंग से नहीं बन पाई। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा-नीत एनडीए सरकार ने पहली बार पूर्वोत्तर में विकास की पहल की और अलग से इसके लिए मंत्रालय का गठन किया, लेकिन उनके बाद कांग्रेस की यूपीए सरकार के 10 वर्षों में पूर्वोत्तर के विकास के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं हुए। 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद पूर्वोत्तर भारत के पूर्ण विकास की नई कहानी लिखी गई है।

पहले पूर्वोत्तर के राज्य उग्रवाद, घुसपैठ, बंद, ब्लॉकेड, ड्रग तस्करी, भ्रष्टाचार और जातीय तनाव की समस्या से आये दिन जूझते रहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूरे नॉर्थ-ईस्ट को अष्टलक्ष्मी का स्वरूप देकर इसे विकास, कनेक्टिविटी, आधारभूत संरचना का विकास, आईटी, औद्योगिक विकास, स्पोर्ट्स, निवेश और जैविक खेती का बड़ा हब बनाया है। नरेन्द्र मोदी ने देश के हर राज्य के संतुलित और तीव्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया ताकि ताकि, देश आत्मनिर्भर बन सके। 'लुक ईस्ट' पॉलिसी के बजाय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 'एक्ट ईस्ट' की पॉलिसी के कारण पिछले 9 वर्षों में पूर्वोत्तर के अष्टलक्ष्मी राज्यों में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला है।

देश की आजादी के बाद सभी प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर जितनी बार गए हैं, प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेन्द्र मोदी अकेले उससे कहीं अधिक बार पूर्वोत्तर जा चुके हैं। इससे यहां विकास को तेज रफ्तार मिल रही है। पूर्वोत्तर को लेकर दिल्ली की सोच में आए इस परिवर्तन का नतीजा है कि पूर्वोत्तर अब भारत के विकास का गेटवे बन रहा है। 'वोकल फॉर लोकल' और 'लोकल फॉर ग्लोबल' के मंत्र ने विकास को गति दी है। लंबे समय तक देश में ये सोच रही है कि बॉर्डर एरिया में विकास होगा तो दुश्मन को फायदा होगा। इस नकारात्मक सोच के कारण पूर्वोत्तर सहित देश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर नहीं हो पाई। अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हीरा (HIRA) अर्थात् हाइवे, इनलैंड वाटरवे, रेलवे और एयरवे के विकास पर जोर दिया है। इससे पूर्वोत्तर के राज्यों, शेष भारत और दिल्ली के बीच की दिल की दूरियां खत्म हुई हैं।

पहले पूर्वोत्तर के राज्य उग्रवाद, घुसपैठ, बंद, ब्लॉकेड, ड्रग तस्करी, भ्रष्टाचार और जातीय तनाव की समस्या से आये दिन जूझते रहते थे लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूरे नॉर्थ-ईस्ट को अष्टलक्ष्मी का स्वरूप देकर इसे विकास, कनेक्टिविटी, आधारभूत संरचना का विकास, आईटी, औद्योगिक विकास, स्पोर्ट्स, निवेश और जैविक खेती का बड़ा हब बनाया है

अभी दिसंबर माह में ही प्रधानमंत्री मोदी ने यहां का दौरा किया था जिसमें उन्होंने हजारों करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की नींव रखी थी। मोदी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में मेघालय के विकास से जुड़ी अनेक रुकावटों को 'रेड कार्ड' दिखाया है। शिलॉन्ग सहित नॉर्थ ईस्ट की सभी राजधानियां रेल-सेवा से जुड़ें, इसके लिए तेज़ी से काम चल रहा है। मेघालय में उड़ान योजना के तहत 16 रूट्स पर हवाई सेवा चल रही है। बेहतर एयर कनेक्टिविटी से मेघालय और नॉर्थ ईस्ट के किसानों को भी लाभ हो रहा है। केंद्र सरकार की कृषि उड़ान योजना से यहां के फल-सब्जी देश और विदेश के मार्केट तक आसानी से पहुंच रहे हैं। पिछले 9 वर्षों में मेघालय में नेशनल हाईवे के निर्माण पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। पिछले 9 वर्षों में जितनी ग्रामीण सड़कें मेघालय में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनी हैं, वह उससे पहले 20 वर्षों में बनी सड़कों से सात गुना अधिक है।

नॉर्थ ईस्ट की युवा शक्ति के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी से नए अवसर बनाए जा रहे हैं। 2014 की तुलना में नॉर्थ ईस्ट में ऑप्टिकल फाइबर की कवरेज लगभग 4 गुणा बढ़ी है। मेघालय में ये वृद्धि 5 गुणा से अधिक है। मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए हजारों मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। मेघालय में IIM का लोकार्पण और टेक्नॉलॉजी पार्क का शिलान्यास भी पढ़ाई और कमाई के अवसरों का विस्तार करेगा। नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी क्षेत्रों में डेढ़ सौ से अधिक एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं, इसमें से 39 मेघालय में हैं। इस बजट में एकलव्य मॉडल स्कूलों में बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती का प्रावधान भी किया गया है। पर्वतमाला योजना से यहां पर्यटन स्थलों में सुविधा बढ़ेगी और टूरिज्म का विकास भी होगा। स्पोर्ट्स को लेकर भी केंद्र सरकार आज एक नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है, जिसका सबसे अधिक लाभ पूर्वोत्तर को हुआ है।

लंबे समय तक देश में जिनकी सरकारें रहीं, उनकी नॉर्थ ईस्ट के लिए 'डिवाइड' की सोच थी और हम 'डिवाइन' (DEVINE)

का इरादा लेकर आए हैं। 'डिवाइन' योजना से कायाकल्प हो रहा है। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं कहा है, हम सभी समुदायों और इलाकों के बीच हर प्रकार के डिवीजन को दूर कर रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट में हम विवादों के बॉर्डर नहीं बल्कि विकास के कॉरिडोर बना रहे हैं। बीते 8 वर्षों में अनेक संगठनों ने हिंसा का रास्ता छोड़ा है, स्थाई शांति की राह पकड़ी है। नॉर्थ ईस्ट में अफस्पा की आवश्यकता न पड़े, इसके लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। राज्यों के बीच दशकों से चले आ रहे सीमा विवाद को सुलझाया जा रहा है। हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट आखिरी छोर नहीं, बल्कि सुरक्षा और समृद्धि के गेट-वे हैं। वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज के तहत सीमावर्ती गांवों में बेहतर सुविधाओं को विकसित करने पर बल दिया जा रहा है।

शांति और विकास की हमारी नीति का सबसे अधिक लाभ जनजातीय समाज को हुआ है। आदिवासी समाज की परंपरा, भाषा-भूषा, खान-पान, संस्कृति को बनाए रखते हुए आदिवासी क्षेत्रों का विकास हमारी प्राथमिकता है। बांस को पेड़ की श्रेणी से हटा कर घास की श्रेणी में लाया गया। इससे बांस से जुड़े आदिवासी उत्पादों के निर्माण को बल मिला। यहां कई वनधन केंद्र स्थापित किए गए हैं। मेघालय में 2 लाख घरों तक पहली बार बिजली पहुंची है, गरीबों के लिए 70 हज़ार से अधिक घर बने हैं, तीन लाख परिवारों को पहली बार नल से जल की सुविधा मिली है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' की नीति पर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार में बिना किसी जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय और क्षेत्र के भेदभाव के सर्वस्पर्शी और सर्व-समावेशी विकास हुआ है। उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम आवास योजना, जल-जीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, सामाजिक सुरक्षा योजना, सौभाग्य योजना आदि योजनाओं के माध्यम से जन-जन का विकास हुआ है। दिसंबर में आई ग्लोबल माइनॉरिटी रिपोर्ट ने माना है कि भारत अल्पसंख्यकों के लिए सबसे अच्छा देश है। रिपोर्ट कहती है कि जिस प्रकार अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक प्रचार के लिए भारत के संविधान में विशेष प्रावधान है, इस तरह के प्रावधान किसी और देश में नहीं है। यह महज एक रिपोर्ट भर नहीं है, बल्कि यह विश्वास और विकास की कहानी है। अक्टूबर, 2021 में प्रधानमंत्री मोदी पवित्र वेटिकन सिटी गए थे, जहां उनकी मुलाक़ात His Holiness the Pope से हुई थी। नरेन्द्र मोदी ने उन्हें भारत आने का निमंत्रण भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं माना कि इस मुलाक़ात ने उनके मन पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इस महत्वपूर्ण बैठक में मानवता के समक्ष चुनौतियों पर चर्चा हुई और इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि एकता और समरसता की भावना से कैसे सबका कल्याण हो सकता है। इसी भाव से भारत आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में यहां के हर नागरिक का सशक्तीकरण सशक्त हो रहा है। ■

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं)

पृष्ठ 14 का शेष...

अब बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बीच सबसे तेजी से बढ़ रही है। यही कारण है कि इसको लेकर दुनिया भर से हमें प्रशंसा एवं सम्मान मिल रहा है और हमारे घनिष्ठ संबंध विकसित हो रहे हैं।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी वैश्विक मित्रता और प्रभाव फल-फूल रहा है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका उन वैश्विक रिश्तों को बदलने में भी विशेष रही है जो पहले नीरस या यहां तक कि विवादास्पद थे। फिर चाहे तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान के साथ संतुलन स्थापित करना हो या अन्य पश्चिम एशियाई इस्लामी राष्ट्रों के साथ नव विकसित संबंध हो, यह सभी प्रधानमंत्री की पहलों के उदाहरण हैं।

लेकिन यह नया भारत भी है, जो अदालती दोस्ती से इतर, शत्रुतापूर्ण कृत्यों का मजबूती से जवाब देने में सक्षम है। जिस प्रकार दुनिया भारत की 'सॉफ्ट पावर' के दोस्ताना रवैये की सराहना करती है, उसी प्रकार चीनी की आक्रामकता और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के प्रति हमारी सोची-समझी लेकिन त्वरित प्रतिक्रियाओं को भी सम्मान के साथ देखा जा रहा है।

भारत की वैश्विक छवि में बदलाव प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आया है। याद करें कि कैसे देश में मौजूद उनके कुछ विरोधियों ने उनकी विभिन्न शुरुआती पहलों को कमतर करके आंकने का प्रयास किया था, जैसेकि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, भारतीय पुनर्जागरण की आकांक्षा को बढ़ावा देना, एक बार फिर से विश्वगुरु बनना, राष्ट्रों के बीच एक उदाहरण पेश करना या विद्वानों, निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करना। प्रधानमंत्री की आलोचना करने वाले इस हद तक चले गए कि उन्होंने सशस्त्र बलों और उनके कठोर कदमों को लेकर भी सवाल उठाया। इस विचार का भी मजाक बनाया गया, जिसके तहत अड़ियल पाकिस्तान जो शांति प्रस्ताव को अस्वीकार करता आया है और सीमा पार आतंकवाद को निरंतर जारी रखें हुए है, को अलग-थलग किया जा सकता है। फिर आज यह वही देश है, जो असहाय हो गया है और जिहादी दबाव, लोकतंत्र दमन के बीच खुद को घिरा हुआ पाता है।

हालांकि भविष्य में भारत और तुर्की के बीच आपसी संबंधों की भविष्यवाणी करना अभी जल्दबाजी होगी, फिर भी स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि भारत की मानवीय पहलों ने मित्रता के दरवाजे खोले हैं। भू-राजनीतिक बदलावों से गुजर रही दुनिया में उभरता हुआ भारत आत्मविश्वास के साथ अपनी भूमिका निभा रहा है और इसका व्यापक रूप से स्वागत किया जा रहा है। ■

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं)

महाशक्ति होने के मार्ग पर मील का पत्थर – बजट 2023-24

गोपाल कृष्ण अग्रवाल

भारत अगर आने वाले समय में अपने आप को विश्वगुरु के स्थान पर देखता है, तो आवश्यक है कि वह आर्थिक महाशक्ति के रूप में खड़ा हो। वैश्विक पटल पर आर्थिक महाशक्ति हुए बिना कोई भी देश हमारे नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेगा। चाहे कूटनीति का क्षेत्र हो या व्यापारिक आदान-प्रदान की संधि, सीमा विवाद, पर्यावरण के विषय, पानी का बंटवारा सभी क्षेत्र में आर्थिक रूप से सशक्त देश की ही बात मानी जाती है। यहां तक कि आयात-निर्यात के विषय भी आर्थिक सक्षमता के आधार पर ही तय किए जाते हैं। आज कूटनीतिक स्तर पर भारत का जो प्रभाव बढ़ रहा है, उसका महत्वपूर्ण कारण भारत की बढ़ती आर्थिक स्थिति है। हम ही नहीं, विश्व भी आज मान रहा है कि आने वाले समय में भारत का आर्थिक विकास बहुत तेज गति से होगा। आने वाले दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व के सकल घरेलू उत्पाद के अनुसार तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। हमारी अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ रही है। हमारे यहां विश्व में सबसे ज्यादा निवेश हो रहा है। अभी हाल में उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 संपन्न हुआ है। उसने दिखा दिया कि भारत में निवेश के लिए विश्व के लोग बहुत लालायित हैं। कुल निवेश का लक्ष्य दस लाख करोड़ रुपये रखा गया था लेकिन अनुबंध साढ़े तैंतीस लाख करोड़ रुपये के हुए हैं। अभी भारत की टाटा समूह की एयरलाइंस एयर इंडिया ने फ्रांस और अमेरिका से 800 हवाई जहाज खरीदने का सौदा किया है, जिसका स्वागत अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति मेक्रोन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद देकर किया।

कोविड महामारी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था महंगाई, मंदी और बजटीय घाटे के चक्रव्यूह में फंस गई है। हर जगह मंदी के संकेत दिखने लगे हैं। चाहे अमेरिका हो, या चीन या यूरोप जैसे विश्व के आर्थिक रूप से विकसित देश हों या फिर पाकिस्तान, श्रीलंका, तुर्की जैसे विकासशील देश सभी के आर्थिक विकास की गति डगमगा गई है। इनके द्वारा कोविड महामारी से निजात पाने के लिए जो नीतियां अपनाई गई थी, वह सकारात्मक परिणाम नहीं ला पाई हैं।

दूसरी ओर, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा अपनाई गई आर्थिक-सामाजिक नीतियों के परिणामस्वरूप भारत आज विश्व की सबसे तीव्र गति से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था बन चुका है और दुनिया में अग्रणी अर्थव्यवस्था वाले देश में शुमार है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार अपना देश महंगाई को नियंत्रित करने में सफल है। दुनिया के अनेक देशों में महंगाई तेजी से बढ़ रही है। हमारी अर्थव्यवस्था मंदी से उभरकर रफ्तार पकड़ चुकी है और अब इस बजट में स्पष्ट कर रूप से वित्तीय घाटे को पाटने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। आने वाले वर्ष में वित्तीय घाटा 5.9% हो जाएगा और वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह 4.5% रहेगा, ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

चाहे फार्मा का क्षेत्र हो, वैक्सीन की बात हो, डिफेंस में तेजस फाइटर प्लेन का निर्यात हो, यूपीआई द्वारा डिजिटल लेनदेन का कार्य हो, ऊर्जा क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा या वैकल्पिक ऊर्जा हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ऑटोमोबाइल का उत्पादन हो, सब क्षेत्रों में भारत अग्रणी भूमिका में आ रहा है। 5जी और कार्बन उत्सर्जन में हम विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं। सड़क निर्माण, रेल मार्ग, संगीत, नृत्य कला, उत्सव आर्किटेक्चर सभी की भारत में समृद्धि के रहते हुए पर्यटन की प्रचुर संभावनाएं हैं। चाहे बहुराष्ट्रीय प्लेटफार्म हो जैसे जी-20, डब्लूईएफ, विश्व व्यापार संगठन, ओईसीडी, क्वाड, एससीओ या संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद् की सदस्यता, सभी में भारत की भूमिका बढ़ती जा रही है। वैश्विक स्तर पर भारत के प्रधानमंत्री की राय सुनी जाती है, मानी जाती है।

द्विराष्ट्रीय व्यापार समझौतों के प्रति भी सभी देशों का रुझान भारत की ओर बढ़ रहा है। हम संयुक्त अरब अमीरात, यूरोप और अमेरिका से व्यापार संधि कर रहे हैं। आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदृष्टि के अनुसार भारत आर्थिक महाशक्ति अवश्य बनेगा। देश में जिस तरह के आर्थिक नीतिगत रिफ़ार्म की आवश्यकता है, उसे मजबूत इच्छाशक्ति के साथ लागू करने वाला यह बजट 2023-24 है। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत श्री नरेन्द्र मोदी सरकार का 2023-24 वाला बजट अमृत काल की आधारशिला रखेगा। और भारत को विश्वगुरु के स्थान पर ले जाने वाला बजट है।

देश में जिस तरह के आर्थिक नीतिगत रिफ़ार्म की आवश्यकता है, उसे मजबूत इच्छाशक्ति के साथ लागू करने वाला यह बजट 2023-24 है। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत श्री नरेन्द्र मोदी सरकार का 2023-24 वाला बजट अमृत काल की आधारशिला रखेगा। और भारत को विश्वगुरु के स्थान पर ले जाने वाला बजट है

सरकार का आधारभूत संरचना के लिए व्यय बढ़ाने पर निरंतर ध्यान केंद्रित रखना अपने देश के चौतरफा विकास को सुनिश्चित करेगा। भारत की मजबूत आर्थिक व्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इस पर कुल पूंजीगत व्यय 33% बढ़ाकर 10 लाख

करोड़ रुपए कर दिया है। देश में बुनियादी सुविधाओं के विकास से आर्थिक तरक्की को तेजी मिलेगी।

इस बार सरकार ने किसी भी प्रकार के नए कर भी नहीं लगाए हैं और सभी करदाताओं को राहत प्रदान की है। अपने आधारभूत संरचना निर्माण व जनकल्याणकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास आवास योजना, छोटे मध्यम और मझोले उद्योगों की सहायता, कृषि एवं सहकारी क्षेत्र को विशेष राहत दी है। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार अगर सरकार आधारभूत क्षेत्र में एक रुपया खर्च करती है तो उससे अर्थव्यवस्था में तीन रुपये के लगभग की मांग सृजित करने की क्षमता होती है और वहीं सरकार द्वारा सीधी आर्थिक मदद में एक रुपये में से पंचानबे पैसे की मांग ही सुनिश्चित हो पाती हैं।

छोटे करदाताओं को विशेष राहत मिली है। सात लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले हर व्यक्ति को शून्य टैक्स देना पड़ेगा। युवाओं के कौशल विकास के लिए केंद्रों का निर्माण, कर्मयोगी योजना में हाथ से काम करने वालों के सशक्तीकरण का विशेष प्रावधान है। भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए वैकल्पिक ऊर्जा जैसे हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और हरित विकास के तहत कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाएगा। नए महत्वपूर्ण क्षेत्र जो आने वाले समय में देश को वैश्विक स्तर पर स्थापित करेंगे जैसे कृत्रिम बुद्धिमता और 5G सेवा पर ध्यान केंद्रित किया गया है और विशेष सहायता सहायता के प्रावधान किये गये हैं। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी बड़ी पहल की गई है। समुद्र के तट पर मैनग्रोव पौधरोपण और नमभूमि में वन संपदा को संरक्षित करने की भी घोषणा महत्वपूर्ण है।

'गरीब कल्याण' हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इस बजट में करीब 2 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान से सभी अंत्योदय वाले परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न देने की योजना को एक साल और बढ़ाने की भी घोषणा की गई है। मत्स्य पालन में शामिल लोगों को सक्षम बनाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में सरकार भंडारण क्षमता बढ़ाएगी। मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी इस बार विशेष योजना 'श्री अन्न' के माध्यम से की गई है इससे किसानों की आय बढ़ेगी और सभी स्वास्थ्य लाभ भी होगा। सामाजिक न्याय प्रक्रिया को सुगम एवं सर्वग्राही बनाने के लिए भी घोषणाएं की गई हैं। ई-कोर्ट की स्थापना की पहल की गई है। कैदियों के मानवाधिकारों को ध्यान में रखते हुए जिनके पास जमानत की राशि की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए सहायता राशि आवंटित की गई है।

गरीब कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इस बजट में करीब 2 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान से सभी अंत्योदय वाले परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न देने की योजना को एक साल और बढ़ाने की भी घोषणा की गई है। मत्स्य पालन में शामिल लोगों को सक्षम बनाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में सरकार भंडारण क्षमता बढ़ाएगी। मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी इस बार विशेष योजना 'श्री अन्न' के माध्यम से की गई है इससे किसानों की आय बढ़ेगी और सभी स्वास्थ्य लाभ भी होगा

दुनिया की निगाहें भारत पर है, क्योंकि हमारा देश G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इस अवसर को ध्यान में रखते हुए पर्यटन के लिए 50 स्थानों पर केंद्र सरकार सभी बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, होटल, कनेक्टिविटी पर खर्च करेगी और संस्कृति, वास्तु क्षेत्र, विभिन्न वेशभूषाएं, भाषाएं, नृत्य, वाद्य सभी कलाओं को वहां प्रोत्साहित किया जाएगा। बजट भारत की विकास यात्रा को जारी रखने वाला है।

इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री का जो संकल्प है, कि आने वाले समय में भारत विश्वगुरु के स्थान पर स्थापित हो, इसके लिए हमें आर्थिक महाशक्ति बनना होगा। यह बजट उसका मार्ग प्रशस्त करने के लिए नींव का पत्थर साबित होगा। अब हमें सामूहिक संकल्प के साथ बजट के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। ■

लेखक भाजपा के आर्थिक मामलों के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं

रक्षा पूंजी खरीद बजट का रिकॉर्ड 75 प्रतिशत हिस्सा घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित

वित्त वर्ष 2023-24 में रक्षा मंत्रालय को कुल 5.94 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जो कुल बजट का 13.18 प्रतिशत (45.03 लाख करोड़ रुपये) है

वित्तीय वर्ष 2023-24 में रक्षा पूंजी खरीद बजट का रिकॉर्ड 75 प्रतिशत (लगभग एक लाख करोड़ रुपये) हिस्सा घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया गया है, जो 2022-23 में 68 प्रतिशत था। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 15 फरवरी, 2023 को बेंगलुरु में 14वें एयरो इंडिया के बंधन समारोह के दौरान इसकी घोषणा की। वित्त वर्ष 2023-24 में रक्षा मंत्रालय को कुल 5.94 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जो कुल बजट का 13.18 प्रतिशत (45.03 लाख करोड़ रुपये) है। आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित पूंजी परिव्यय को बढ़ाकर 1.63 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। ■

भारत वैश्विक स्तर पर एक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हुआ : जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 22 फरवरी, 2023 को सुषमा स्वराज भवन, नई दिल्ली में "मोदीः शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स" पुस्तक का लोकार्पण किया और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक परिवेश में भारत के बढ़ते कद और वैश्विक समस्याओं के समाधान में भारत की अग्रणी भूमिका पर विस्तार से चर्चा की। "मोदीः शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स" की प्रस्तावना भारत के विदेश मंत्री श्री एस. जयशंकर जी ने लिखी है जबकि इसके संपादक श्री सुजान चिनॉय (मनोहर परिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के महानिदेशक), श्री विजय चौथाईवाले (भाजपा के विदेश मामलों के प्रभारी) और श्री उत्तम कुमार सिन्हा (मनोहर परिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में फेलो और प्रसिद्ध शिक्षाविद) हैं।

श्री नड्डा ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी ने विदेश नीति और विदेश मामलों को बेहतरीन तरीके से दिशा-निर्देशित किया। दुनिया के कई देशों से भारत के संबंध शुरुआत से ही प्रगाढ़ रहे हैं लेकिन कई दशकों से भारतीय प्रधानमंत्री उन देशों में गए ही नहीं थे और इस तरह मित्र देशों के साथ भी हमारे संबंधों में शिथिलता आ गई थी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस खाई को पाटा और पड़ोसी देशों के साथ-साथ अन्य देशों और खाड़ी के देशों के साथ भी संबंध को और प्रगाढ़ किया। हमारी सरकार आने से पहले इजरायल जाने की हिम्मत किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं की। ऐसा केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति की वजह से हुआ। श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के हितों को तरजीह दी और इजरायल के साथ सुरक्षा संबंधों को और मजबूत बनाया। साथ ही, उन्होंने फिलिस्तीन के साथ भी संबंधों को प्रमुखता दी। उन्होंने अपनी विदेश नीति को इस बात के केंद्र में रखा कि किस तरह भारतीय चिंतन को लेकर देश वैश्विक स्तर पर एक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हो। पिछले साढ़े 8 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 100 से अधिक विशेष यात्राएं करके 60 से अधिक देशों की यात्रा की। उन्होंने सभी पड़ोसी देशों की भी यात्राएं की। इससे पड़ोसी देशों और भारत के बीच आपसी समझ बेहतर हुई। ■

भारतीय रेल ने रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस माल सेवा का किया शुभारंभ

पहली बार माल भाड़ा प्रति किलोग्राम-प्रति किलोमीटर के आधार पर तय किया जायेगा

भारतीय रेलवे और इंडिया पोस्ट ने औपचारिक रूप से रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस माल सेवा संयुक्त पार्सल उत्पाद का शुभारंभ किया है। यह देश में सेवा क्षेत्र के लिए निर्बाध लॉजिस्टिक्स प्रदान करने में भारतीय रेल और इंडिया पोस्ट के बीच साझेदारी की एक पहल है। यह वित्त वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के अनुपालन में है। 16 फरवरी को इसे चार सेक्टरों पर शुरू किया गया— दिल्ली से कोलकाता; बैंगलोर से गुवाहाटी, सूरत से मुजफ्फरपुर और हैदराबाद से हजरत निजामुद्दीन। तथापि, पहले चरण में कुल 15 क्षेत्रों को शामिल करने की योजना बनाई गई है।

इस सेवा की मुख्य विशेषताएं कुल लॉजिस्टिक सेवा हैः ग्राहक परिसर में पिक-अप और डिलीवरी, पैलेटाइजेशन— कवर और सील किए गए बक्से के माध्यम से परिवहन, अर्ध-मशीनीकृत हैंडलिंग, समय-सारिणी आधारित सेवा, नुकसान, क्षति और एकीकृत पार्सल बीमा के मद्देनजर घोषित मूल्य के 0.05 प्रतिशत पर बीमा आदि। इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए डाक और रेलवे के बीच संयुक्त विपणन दल बनाए गए हैं। मूल्य निर्धारण की स्लैब प्रणाली को खत्म करना यहां एक नवाचार के रूप में है।

रेल और डाक विभाग ने सामूहिक रूप से सर्वोत्तम उपयोग के लिए अपने उपकरणों, मशीनरी और हैंडलिंग उपकरण, भंडारण स्थान को अपग्रेड किया है। विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए फोल्ड टाइप बॉक्स, लिफाफा बॉक्स, मेश टाइप बॉक्स, एल्यूमीनियम और हल्के वजन वाली सामग्री से बने बबल गार्ड बॉक्स विकसित किए गए हैं। इसी प्रकार, पार्सल एकत्रीकरण केंद्र को कुशल स्टैकिंग के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए रेक के साथ कन्वेयर सिस्टम से लैस किया गया है। बीटीयू डेक में सहज आवागमन के लिये पैलेटाइज्ड सामग्री को आसानी से रोल किया जा सकता है। ■

प्रधानमंत्री ने तुर्किए और सीरिया में 'ऑपरेशन दोस्त' में शामिल एनडीआरएफ कर्मियों के साथ की बातचीत

भूकंप प्रभावित तुर्किए और सीरिया में 'ऑपरेशन दोस्त' के तहत राहत व बचाव कार्य कर एनडीआरएफ की टीम भारत लौट आई। दरअसल, तुर्किए और सीरिया में छह फरवरी को आए भीषण भूकंप के चलते 46,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई तथा लाखों लोग घायल व बेघर हो गए। इस मुश्किल की घड़ी में भारत सरकार ने बिना देर किये 'ऑपरेशन दोस्त' के तहत मदद भेजनी शुरू कर दी।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक ट्वीट में कहा कि 151 एनडीआरएफ कर्मियों और श्वान दस्तों की तीन टीम ने भूकंप प्रभावित तुर्किए की मदद की। उन्होंने कहा कि टीम ने नूरदागी और अंताक्या के 35 स्थलों पर जीवित लोगों का पता लगाने सहित खोज, बचाव और राहत अभियान चलाया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 20 फरवरी को भूकंप प्रभावित तुर्किए और सीरिया में 'ऑपरेशन दोस्त' में शामिल राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कर्मियों से बातचीत की। कर्मियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने भूकंप प्रभावित तुर्किए और सीरिया में 'ऑपरेशन दोस्त' के तहत किए गए शानदार कार्यों के लिए उनकी प्रशंसा की। श्री मोदी ने भारत की वसुधैव कुटुम्बकम् की अवधारणा के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि तुर्किए और सीरिया में भारतीय दल ने हमारे लिए 'पूरी दुनिया एक परिवार है', की भावना का प्रकटीकरण किया।

प्राकृतिक आपदा के समय जल्द प्रतिक्रिया के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्री मोदी ने 'गोल्डन ऑवर' का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि तुर्किए में एनडीआरएफ की टीम जितनी जल्दी वहां पहुंची, इसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। श्री मोदी ने कहा कि यह दल की तैयारी और प्रशिक्षण की कुशलता को दिखाता है।

प्रधानमंत्री ने एक मां की तस्वीर की चर्चा की, जो टीम के सदस्यों का माथा चूमकर आशीर्वाद दे रही थी। श्री मोदी ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों से बचाव और राहत कार्यों की आने वाली तस्वीरों को देखने के बाद हर भारतीय ने गर्व का अनुभव किया। उन्होंने कहा कि बेजोड़ पेशेवर अंदाज के साथ-साथ मानवीय संवेदनाओं का जो समावेश किया गया, वह अतुलनीय है।

तुर्किए और सीरिया में भारतीय दल ने
' वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना का प्रकटीकरण किया

दूसरे देशों के नागरिकों के लिए भी ढाल बना 'तिरंगा'

यूक्रेन में तिरंगा की भूमिका का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा लेकर हम जहां भी पहुंचते हैं, वहां एक आश्वासन मिल जाता है कि अब भारत की टीमें आ चुकी हैं, हालात ठीक होना शुरू हो जाएंगे। श्री मोदी ने स्थानीय लोगों के बीच तिरंगे को मिले सम्मान का भी जिक्र किया। उन्होंने याद किया कि कैसे ऑपरेशन गंगा के दौरान यूक्रेन में भारतीय नागरिकों के साथ-साथ दूसरे देशों के नागरिकों के लिए भी तिरंगा ढाल बना।

श्री मोदी ने 'ऑपरेशन दोस्त' के माध्यम से मानवता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि जब तुर्किए और सीरिया में भूकंप आया, तो भारत सबसे पहले मदद लेकर पहुंचने वालों में से एक था। उन्होंने नेपाल में भूकंप, मालदीव और श्रीलंका में संकट का उदाहरण दिया और कहा कि भारत सबसे पहले मदद के लिए आगे आया। श्री मोदी ने कहा कि अब तो भारत की सेनाओं के साथ-साथ एनडीआरएफ पर भी देश के अलावा दूसरे देशों का भरोसा बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि बीते वर्षों में एनडीआरएफ ने देश के लोगों में एक बहुत अच्छी साख बनाई है।

उन्होंने कहा कि देश के लोग एनडीआरएफ पर विश्वास करते हैं। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि जैसे ही एनडीआरएफ की टीम पहुंचती है लोगों की उम्मीद और विश्वास लौट आता है, यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब किसी बल में कुशलता के साथ संवेदनशीलता जुड़ जाती है तो उस बल की ताकत कई गुना बढ़ जाती है।

संबोधन के आखिर में श्री मोदी ने एनडीआरएफ दल के प्रयासों और अनुभवों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भले ही वे वहां बचाव अभियान चला रहे थे, लेकिन वह पिछले 10 दिनों से लगातार दिल और दिमाग से उनसे जुड़े हुए थे। ■

प्रधानमंत्री ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का किया उद्घाटन

'आज भारत बाध्यता से नहीं, बल्कि संकल्प के साथ सुधार कर रहा है'

जैसे भारत वैश्विक मंच पर एक उज्ज्वल देश के रूप में उभरा है, वैसे ही यूपी भी देश के लिए एक उज्ज्वल राज्य बन गया है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 10 फरवरी को लखनऊ में उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ग्लोबल ट्रेड शो का भी उद्घाटन किया और इन्वेस्ट यूपी 2.0 लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रमुख निवेश शिखर सम्मेलन है, जो व्यापार के अवसरों का सामूहिक रूप से पता लगाने और साझेदारी बनाने के लिए दुनिया भर के नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, थिंक टैंक और राजनेताओं को एक मंच पर लाता है। प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया।

5-6 साल में उत्तर प्रदेश ने एक नई पहचान बनाई है। अब उत्तर प्रदेश सुशासन, बेहतर कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता के लिए जाना जाता है

सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने निवेशक समुदाय, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और नीति निर्माताओं का प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश से संसद सदस्य, दोनों रूपों में स्वागत किया।

5-6 साल में उत्तर प्रदेश ने एक नई पहचान बनाई है

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि उत्तर प्रदेश की धरती अपने सांस्कृतिक वैभव, गौरवशाली इतिहास और समृद्ध विरासत के लिए जानी जाती है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि 5-6 साल में उत्तर प्रदेश ने एक नई पहचान बनाई है। अब उत्तर प्रदेश सुशासन, बेहतर कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि धन सृजित करने वालों के लिए यहां नए अवसर बनाए जा रहे हैं।

श्री मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि उत्तर प्रदेश में बेहतर अवसंरचना के बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द यूपी 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाले एकमात्र राज्य के रूप में जाना जाएगा। फ्रेट कॉरिडोर राज्य को सीधे महाराष्ट्र के समुद्री तट से जोड़ेगा।

श्री मोदी ने 'कारोबार में आसानी' सुनिश्चित करने के लिए यूपी में सरकार की सोच में सार्थक बदलाव आने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश आशा और प्रेरणा का स्रोत बन गया है। श्री मोदी ने रेखांकित किया कि जैसे भारत वैश्विक मंच पर एक उज्ज्वल देश के रूप में उभरा है, वैसे ही यूपी भी देश के लिए एक उज्ज्वल राज्य बन गया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल क्रांति के कारण उत्तर प्रदेश का समाज समावेशी और संपर्क सुविधा से युक्त है। उन्होंने कहा कि एक बाजार के रूप में भारत सहज हो रहा है। प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जा रहा है। आज भारत बाध्यता से नहीं, बल्कि संकल्प के साथ सुधार कर रहा है।

सिर्फ ऊर्जा बदलाव के लिए 35 हजार करोड़ रुपए आवंटित

बजट पर चर्चा करते हुए श्री मोदी ने अवसंरचना के बढ़ते आवंटन को रेखांकित किया और निवेशकों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक बुनियादी ढांचे के अवसरों के बारे में बात की। इसी तरह, उन्होंने निवेशकों को भारत द्वारा अपनाये गए हरित विकास पथ से जुड़े अवसरों के लिए आमंत्रित किया। श्री मोदी ने बताया कि इस साल के बजट में सिर्फ ऊर्जा बदलाव के लिए 35 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

श्री मोदी ने राज्य में मौजूद पारंपरिक और आधुनिक एमएसएमई के जीवंत नेटवर्क का उल्लेख किया और भदोही और वाराणसी के रेशम का उदाहरण दिया, जिसने यूपी को भारत का वस्त्र केंद्र बना दिया है।

उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा मोबाइल कल-पुर्जों के साथ भारत के 60 प्रतिशत मोबाइल फोन यूपी में निर्मित होते हैं। श्री मोदी ने इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि देश के दो रक्षा कॉरिडोर में से एक यूपी में विकसित हो रहा है।

फसल विविधीकरण, किसानों को अधिक संसाधन और लागत कम करने पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक खेती पर ध्यान केंद्रित करने पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि यूपी में गंगा के दोनों किनारों के 5 किमी तक प्राकृतिक खेती शुरू हो गई है।

इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, विदेशी गणमान्य व्यक्ति और उद्योग जगत के प्रतिनिधि उपस्थित थे। ■

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' को दी मंजूरी

यह योजना देश की उत्तरी भूमि सीमा के साथ 19 जिलों और 46 सीमा ब्लॉकों, 4 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में आवश्यक अवसंरचना विकास व आजीविका के अवसरों के निर्माण के लिए धन प्रदान करेगी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 फरवरी को वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए 4800 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के साथ केंद्र प्रायोजित योजना 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' (वीवीपी) को मंजूरी दी।

उल्लेखनीय है कि उत्तरी सीमा पर ब्लॉकों के गांवों के व्यापक विकास से चिन्हित सीमावर्ती गांव में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। इससे लोगों को सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने मूल स्थानों पर रहने के लिए प्रोत्साहित करने तथा इन गांवों से पलायन रोकने में सहायता मिलेगी, सीमा की सुरक्षा में सुधार होगा।

यह योजना देश की उत्तरी भूमि सीमा के साथ 19 जिलों और 46 सीमा ब्लॉकों, 4 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में आवश्यक अवसंरचना विकास व आजीविका के अवसरों के निर्माण के लिए धन प्रदान करेगी, जिससे समावेशी विकास हासिल करने तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या को बनाए रखने में सहायता मिलेगी। इस कार्यक्रम के पहले चरण में 663 गांवों को शामिल किया जाएगा।

इस योजना का उद्देश्य उत्तरी सीमा के सीमावर्ती गांव में स्थानीय प्राकृतिक मानव और अन्य संसाधनों के आधार पर आर्थिक प्रेरकों की पहचान और विकास करना तथा सामाजिक उद्यमिता प्रोत्साहन, कौशल विकास तथा उद्यमिता के माध्यम से युवाओं व महिलाओं को सशक्त बनाकर 'हब एंड स्पोक मॉडल' पर विकास केंद्रों को विकसित करना, स्थानीय संस्कृति, पारंपरिक ज्ञान और विरासत प्रोत्साहन के माध्यम से पर्यटन क्षमता का लाभ उठाना और समुदाय आधारित संगठनों, सहकारिता, एसएचजी, एनजीओ के माध्यम से 'एक गांव एक उत्पाद' की अवधारणा पर स्थायी इको-एग्री बिजनेस का विकास करना है।

वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान ग्राम पंचायतों की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा तैयार किया जाएगा। केंद्रीय तथा राज्य योजनाओं की शत-प्रतिशत पूर्णता सुनिश्चित की जाएगी। जिन प्रमुख उद्देश्यों को हासिल करने का प्रयास किया गया है उनमें सभी मौसम अनुकूल सड़क, पेयजल, 24X7 सौर तथा पवन ऊर्जा पर केंद्रित विद्युत आपूर्ति, मोबाइल तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी, पर्यटक केंद्र, बहुद्देशीय सेंटर तथा स्वास्थ्य एवं वेलनेस सेंटर शामिल हैं।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के साथ किसी तरह की अंशतः समानता नहीं होगी। 4800 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन में से 2500 करोड़ रुपए का उपयोग सड़कों के लिए किया जाएगा। ■

वर्ष 2022-23 के लिए 3235.54 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित

चावल, गेहूं, मक्का, चना, मूंग, रेपसीड एवं सरसो और गन्ने का रिकार्ड उत्पादन अनुमानित

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि वर्ष 2022-23 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान जारी कर दिए गए। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 14 फरवरी को बताया कि वर्तमान कृषि वर्ष में 3235.54 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है।

श्री तोमर ने अग्रिम अनुमानों में मोटे अनाज के उत्पादन में वृद्धि की सराहना करते हुए आशा जताई कि आने वाले वर्षों में मोटे अनाज/पोषक अनाज के उत्पादन और प्रयोग में और अधिक वृद्धि होगी।

गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मोटे अनाज के वर्ष के रुप में मनाने की घोषणा की थी। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मोटे अनाज/पोषक अनाज को 'श्री अन्न' का नाम दिया है।

वर्ष 2022-23 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 3235.54 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले वर्ष 2021-22 की तुलना में 79.38 लाख टन अधिक है।

वर्ष 2022-23 के दौरान चावल का कुल उत्पादन (रिकॉर्ड) 1308.37 लाख टन अनुमानित है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 13.65 लाख टन अधिक है। देश में गेहूं का उत्पादन (रिकॉर्ड) 1121.82 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में 44.40 लाख टन अधिक है।

वर्ष 2022-23 के दौरान देश में मक्का का उत्पादन रिकॉर्ड 346.13 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले वर्ष के 337.30 लाख टन उत्पादन की तुलना में 8.83 लाख टन अधिक है। श्री अन्न (पोषक-अनाज) का उत्पादन 527.26 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में 16.25 लाख टन अधिक है। ■

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 फरवरी को दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत सरकार और दक्षिण अफ्रीका सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी।

द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन दिव्यांगता के क्षेत्र में संयुक्त पहल के माध्यम से दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, भारत सरकार और दक्षिण अफ्रीका सरकार के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करेगा। यह भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा। दोनों देशों के बीच सहयोग के विशिष्ट प्रस्तावों, जैसाकि पारस्परिक रूप से सहमत है, समझौता ज्ञापन की वैधता की अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए लिया जाएगा।

इसमें परिकल्पना की गई है कि दोनों देशों में बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी), जिन्हें विशेष रूप से आधुनिक, वैज्ञानिक, टिकाऊ, कम लागत वाली सहायक सामग्री और सहायक उपकरणों की आवश्यकता है, इस समझौता ज्ञापन से लाभान्वित होंगे।

स्वतंत्रता और न्याय के लिए संघर्ष के संदर्भ में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक लंबी ऐतिहासिक कड़ी और संबंध हैं, जब महात्मा गांधी ने एक सदी पहले दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। रंगभेद विरोधी आंदोलन के समर्थन में भारत अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भी सबसे आगे था। स्वतंत्रता के बाद 1993 में दक्षिण अफ्रीका के साथ राजनयिक संबंध बहाल हुए और उसके बाद भारत और दक्षिण अफ्रीका ने मार्च, 1997 में एक रणनीतिक साझेदारी की। इसके बाद द्विपक्षीय और ब्रिक्स, आईबीएसए और अन्य फोरम के माध्यम से दक्षिण अफ्रीका के साथ हमारे घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध मजबूत हुए।

दोनों देशों के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग, रक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, मानव आवासन, लोक प्रशासन एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में कई द्विपक्षीय समझौते हुए हैं। भारत का तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (आईटीईसी) मानव संसाधनों के विकास में सहयोग को बढ़ावा देने का एक उपयोगी माध्यम रहा है।

कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने और अन्य वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय सहयोग उल्लेखनीय रहा है। विभिन्न अन्य मंत्रालयों/विभागों ने भी अपने संबंधित क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों/समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो दक्षिण अफ्रीका सरकार के साथ मजबूत संबंधों को दर्शाते हैं। ■

देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान करने और इसे व्यापक बनाने को मिली मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 फरवरी को देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान करने और इसकी पहुंच को जमीनी स्तर तक व्यापक बनाने को मंजूरी दी।

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के सक्षम मार्गदर्शन में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के समन्वय के माध्यम से 'संपूर्ण-सरकार' वाले दृष्टिकोण का लाभ उठाते हुए व्यवहार्य प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) से वंचित प्रत्येक पंचायत में उनकी स्थापना करने, व्यवहार्य डेयरी सहकारी समितियों से वंचित प्रत्येक पंचायत/गांव में उनकी स्थापना करने और प्रत्येक तटीय पंचायत/गांव के साथ-साथ विशाल जलाशयों वाली पंचायत/गांव में मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना करने और मौजूदा पीएसीएस/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों को मजबूती प्रदान करने की योजना तैयार की है।

प्रारंभ में अगले पांच वर्षों में 2 लाख पीएसीएस/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना की जाएगी। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए नाबार्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) द्वारा कार्य योजना तैयार की जाएगी।

चालू योजना के अंतर्गत समन्वय के लिए निम्न योजनाओं की पहचान की गई है:

क. पशुपालन और डेयरी विभाग:

i. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) और

ii. डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष (डीआईडीएफ)

ख. मत्स्य पालन विभाग:

i. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) और

ii. मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (एफआईडीएफ)

यह योजना देश भर में सदस्य किसानों को उनकी उपज का विपणन करने, उनकी आय बढ़ाने, ग्राम स्तर पर ही ऋण सुविधाएं और अन्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए आवश्यक फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज प्रदान करेगी। पुनर्जीवित नहीं की जा सकने वाली प्राथमिक सहकारी समितियों को बंद करने के लिए चिन्हित किया जाएगा और उनके परिचालन के क्षेत्र में नई प्राथमिक सहकारी समितियों की स्थापना की जाएगी। ■

वैश्विक विकास में 15 प्रतिशत योगदान के साथ भारत वर्ष 2023 के लिए एक 'ब्राइट स्पॉट' बना हुआ है: आईएमएफ

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने कहा कि भारत विश्व अर्थव्यवस्था में एक 'ब्राइट स्पॉट' बना हुआ है और 2023 में वैश्विक विकास में अकेले 15 प्रतिशत का योगदान देगा।

एक ओर जहां डिजिटलीकरण ने दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को महामारी के दुष्परिणामों से बाहर निकाला, वहीं विवेकपूर्ण राजकोषीय नीति और बजट में प्रदान किए गए पूंजीगत निवेश के लिए महत्वपूर्ण वित्तपोषण विकास की गति को बनाए रखने में मदद करेंगे।

भारत का प्रदर्शन काफी प्रभावशाली रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि मार्च में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए भारत उच्च विकास दर 6.8 प्रतिशत को बनाए रखेगा। वित्त वर्ष 2023-24 (अप्रैल, 2023 से मार्च, 2024) के लिए हमारा अनुमान 6.1 प्रतिशत विकास दर का है। यह वैश्विक औसत से काफी ऊपर है।

भारत का प्रदर्शन काफी प्रभावशाली रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि मार्च में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए भारत उच्च विकास दर 6.8 प्रतिशत को बनाए रखेगा। वित्त वर्ष 2023-24 (अप्रैल 2023 से मार्च 2024) के लिए हमारा अनुमान 6.1 प्रतिशत विकास दर का है

यह प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज विकास दर है। भारत ऐसे समय में एक 'ब्राइट स्पॉट' बना हुआ है जब आईएमएफ 2023 को मुश्किल होने का अनुमान लगा रहा है। वैश्विक विकास पिछले साल के 3.4 प्रतिशत से घटकर 2023 में 2.9 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। ■

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बनें

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चेक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चेक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

नई दिल्ली में 20 फरवरी, 2023 को तुर्की और सीरिया में 'ऑपरेशन दोस्त' में शामिल एनडीआरएफकर्मियों के साथ बातचीत करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

बेंगलुरु में 13 फरवरी, 2023 को 'एयरो इंडिया 2023' के 14वें संस्करण के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम (नई दिल्ली) में 16 फरवरी, 2023 को आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

21 फरवरी, 2023 को भारत और सिंगापुर के बीच यूपीआई-पे नाउ लिंकेज की शुरुआत करते सिंगापुर के प्रधानमंत्री श्री ली सियन लूंग और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

14 फरवरी, 2023 को बातचीत के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कमल संदेश

अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध

लॉग इन करें:

www.kamalsandesh.org

राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

@Kamal.Sandesh
@KamalSandesh
kamal.sandesh
KamalSandeshLive

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली "रजिस्टर्ड"
36 पृष्ठ कवर सहित
आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2021-23
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2021-23

आवरण: अजय कुमार सिंह